। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।

● वर्ष-6
● अंक-37
रायपुर, बुधवार 16 सितंबर 2026
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

पेज-8>> विश्व सर्कुलर इकोनॉमी...

शेख हसीना की पार्टी के सात नेताओं को फांसी की सजा

बांग्लादेश। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल-2 ने मंगलवार को प्रतिबंधित अवामी लीग के सात वरिष्ठ नेताओं को मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में मौत की सजा सुनाई। इन नेताओं पर 2024 में छात्र नेतृत्व वाले प्रदर्शनों, जिन्हें 'जुलाई विद्रोह' के नाम से जाना जाता है, के दौरान हिंसा का निर्देश देने, उसे भड़काने या उसे बढ़ावा देने में भूमिका निभाने का आरोप था। तीन सदस्यीय ट्रिब्यूनल की अध्यक्षता कर रहे न्यायमूर्ति मोहम्मद नजरुल इस्लाम चौधरी ने सातों के खिलाफ फैसला सुनाया। सभी आरोपियों पर मुकदमा उनकी गैरमौजूदगी में चला। मौत की सजा पाने वालों में अवामी लीग के महासचिव और पूर्व सड़क परिवहन मंत्री ओबैदुल कादेर, संयुक्त महासचिव एएफएम बहाउद्दीन नसीम और पूर्व सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री मोहम्मद अली अराफात शामिल हैं। इनके अलावा जुबो लीग के अध्यक्ष शेख फजले शम्स परश, महासचिव मैनुल हुसैन खान निखिल, बांग्लादेश छात्र लीग के अध्यक्ष साद्दाम हुसैन और महासचिव शेख वली आसिफ एनान को भी मौत की सजा सुनाई गई है। ट्रिब्यूनल के फैसले के दौरान सातों आरोपियों की ओर से सरकार द्वारा नियुक्त बचाव पक्ष के वकील मौजूद थे। यह मामला 2024 के उन प्रदर्शनों से जुड़ा है, जिनके करीब 10 महीने बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को भी गैरमौजूदगी में मौत की सजा सुनाई गई थी।

जो भूपेश बघेल नहीं कर पाए वो सचिन पायलट ने कर दिखाया?

एक मंच पर दिखे चन्नी-राजा

चंडीगढ़। चंडीगढ़ के सेक्टर 15 में पंजाब कांग्रेस भवन के बाहर कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। पंजाब कांग्रेस के नए प्रभारी और राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी वहां पहुंच गए हैं। तीन महीने बाद, पूर्व सीएम और जालंधर के सांसद चरणजीत चन्नी और राज्य कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग एक ही मंच पर साथ दिखे। खास बात यह है कि दोनों नेता बहुत गर्मजोशी से बातचीत करते हुए भी दिखे; उनके बीच की अच्छी केमिस्ट्री ने सबका ध्यान खींचा। इससे पहले, चन्नी और सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पंजाब कांग्रेस के पूर्व प्रभारी भूपेश बघेल से साफ़ कह दिया था कि वे पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में राजा वडिंग के साथ मंच साझा नहीं करेंगे। हालाँकि, अब ये सभी नेता सचिन पायलट के नेतृत्व में हो रहे इस विरोध प्रदर्शन में एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी सचिन पायलट के दाईं ओर बैठे हैं और उनके बाईं ओर राजा वडिंग बैठे हैं। इस दौरान चन्नी और राजा वडिंग को बातचीत करते हुए देखा गया। जैसे ही मंच से चन्नी का नाम घोषित किया गया, पार्टी कार्यकर्ताओं ने नारे लगाना शुरू कर दिया। हालाँकि, चन्नी ने अपने भाषण के दौरान एक बार भी राजा वडिंग का नाम नहीं लिया।

इस बीच, विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा देखिए, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता एक ही मंच पर जमा हुए हैं। उन्होंने कहा कि वे किसी खास चेहरे को आगे किए बिना चुनाव लड़ेंगे; इसके बजाय, वे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और सचिन पायलट के नाम पर वोट मांगेंगे। बहुमत मिलने के बाद हाई कमान फैसला करेगा। जब पिता जीवित हों, तो बेटों का कोई दावा नहीं बनता। इससे पहले, जैसे ही राजा वडिंग ने माइक संभाला, एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने अपने झंडे लहराए। राजा वडिंग उन्हें बार-बार बैठने के लिए कहते रहे, लेकिन वे झंडे लहराते रहे। राजा वडिंग ने सबसे पहले सचिन पायलट का नाम लिया, उसके बाद बाजवा का। फिर उन्होंने चन्नी का नाम लिया और उसके बाद सुखजिंदर रंधावा का।

पायलट ने बदलाव की संभावना से इनकार नहीं किया

कांग्रेस हाईकमान ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की जगह सचिन पायलट को पंजाब कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त किया है। पंजाब का दौरा शुरू करने से पहले ही, पायलट ने कांग्रेस में और संगठनात्मक बदलावों की संभावना से इनकार नहीं किया। पायलट ने कहा कि पार्टी का अभी पूरा ध्यान पंजाब में बहुमत के साथ सरकार बनाने पर है। उन्होंने संगठनात्मक जिम्मेदारियों में बदलाव को एक सामान्य प्रक्रिया बताया इस टिप्पणी ने निश्चित रूप से वारिंग को लेकर अटकलों को हवा दी है।

ट्रैफ़िक पुलिस ने एडवाइज़री जारी की

कांग्रेस के इस विरोध प्रदर्शन को देखते हुए, चंडीगढ़ ट्रैफ़िक पुलिस ने एक एडवाइज़री जारी की है। सुबह 11.30 बजे से सेक्टर 15/16 लाइट पॉइंट और जीएमएसएच सेक्टर 16 राउंडअबाउट के बीच के रास्ते पर, साथ ही जीएमएसएच सेक्टर 16 राउंडअबाउट से पीजीआई राउंडअबाउट तक मध्य मार्ग पर ट्रैफ़िक प्रभावित रहेगा। लोगों से वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करने की अपील की गई है।

राजधानी रायपुर के तेलीबांधा मरीन ड्राइव में सड़क किनारे पसरा लगाकर मिट्टी के दीये बेच रही मीरा के लिए आज का दिन अचानक बेहद खास बन गया। रोज की तरह वह अपने छोटे से पसरे पर दीये सजाकर ग्राहकों की प्रतीक्षा कर रही थी। इसी बीच मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का काफिला अचानक उसके पसरे के पास जाकर रुक गया। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने मीरा के पसरे पर रखे मिट्टी के दीयों को देखा और 'सेवा संकल्प अभियान' के अंतर्गत आयोजित होने वाले 'आशीर्वाद का दीया' कार्यक्रम के लिए वहीं से एक दीया खरीदा।

यूपीआई पेमेंट पर 20 और 40 रुपए कटेंगे

नई दिल्ली। डिजिटल ट्रांजैक्शंस पर शुल्क लगाए जाने को लेकर उठे विरोध के बीच सरकार ने यूपीआई पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) को लेकर नया फैसला लिया है. सरकार के अनुसार, 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई भुगतान पर मर्चेंट्स को 0.4 प्रतिशत शुल्क देना होगा.

एनपीसीआई ने मंगलवार को बताया है कि 15 अक्टूबर से यूपीआई के जरिए 2 हजार रुपये के ट्रांजैक्शन पर व्यापारियों को 0.4 प्रतिशत की फीस देना होगी. वहीं सोमवार को ही सरकार ने साफ किया था कि 2000 रुपये तक के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर बैंक या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष शुल्क नहीं लगा सकते. इस शुल्क को मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) कहा जाता है. ये शुल्क 0.4% होगा, लेकिन इसकी अधिकतम सीमा 300 रुपये पर ट्रांजैक्शन तय की गई है. इसका मतलब है कि अगर कोई ग्राहक

15 अक्टूबर से होगा लागू

किसी व्यापारी को 75,000 रुपये या उससे ज्यादा का यूपीआई पेमेंट करता है, तो 0.4% के हिसाब से उस पर 300 रुपये से ज्यादा शुल्क बन सकता है, लेकिन व्यापारी से अधिकतम 300 रुपये ही एमडीआर शुल्क लिया जाएगा.

15 अक्टूबर 2026 से चुनिंदा मर्चेंट ट्रांजेक्शन के लिए यूपीआई मर्चेंट डिस्काउंट रेट का नया फ्रेमवर्क लागू होगा. साथ ही, ग्राहकों के लिए 2 हजार रुपये तक के सभी ट्रांजैक्शन के लिए यूपीआई पूरी तरह से फ्री रहेगा. नए नियमों के तहत, क्यूआर कोड के ज़रिए हर महीने 1 लाख रुपये तक कमाने वाले छोटे मर्चेंट को कोई एमडीआर नहीं देना होगा. इसके अलावा रेलवे और फ्यूल जैसी खास कैटेगरी में 2000 रुपये से ज्यादा के ट्रांजैक्शन पर 5 रुपये की फ्लैट फीस लगेगी, और दूसरे ज्यादा वैल्यू वाले पी2एम ट्रांजेक्शन पर 0.4% चार्ज लगेग।

व्यापारियों पर पड़ेगा असर

इस नए नियम से उन व्यापारियों पर सीधा असर पड़ेगा जो 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेनदेन स्वीकार करते हैं। उन्हें प्रत्येक ऐसे लेनदेन पर 0.4 फीसदी का शुल्क देना होगा। हालांकि, 75,000 रुपये से अधिक के बड़े भुगतानों के लिए शुल्क 300 रुपये तक सीमित रहेगा। यह शुल्क व्यापारियों के लिए एक नई लागत होगी। इसका उद्देश्य यूपीआई प्रणाली को आत्मनिर्भर बनाना है।

मसूद अजहर पर पाक के 70 लाख वाले इनामी खेल की भारत ने खोली पोल

नई दिल्ली। भारत ने जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अज़हर पर इनाम की राशि बढ़ाने के पाकिस्तान के कदम को दिखावा और झूठी घोषणा करार दिया और इस्लामाबाद से कहा कि वह खोखली घोषणाएं करने के बजाय ठोस कार्रवाई करे। पाकिस्तान की फ़ेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपनी 2026 की सबसे ज़्यादा वांछित आतंकवादियों की सूची में जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अज़हर का नाम शामिल किया है। उसे पकड़ने में मदद करने वाली जानकारी के लिए इनाम की राशि भी 20 लाख पाकिस्तानी रुपये से बढ़ाकर 70 लाख पाकिस्तानी रुपये कर दी गई है।

एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसे आंख में धूल झोंकने वाली हरकत (धोखा देने की कोशिश) बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ओर से इस तरह के हथकंडे और लोगों को गुमराह करने की कोशिशें कोई नई बात नहीं हैं। हमने पहले भी ऐसे हथकंडे देखे हैं। उन्होंने आगे कहा आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश की ओर से ऐसी झूठी घोषणाएं किए जाने पर हम सभी जानते हैं कि वे कितनी खोखली होती हैं। पाकिस्तान को ऐसी घोषणाएं करने के बजाय ठोस कदम उठाने चाहिए, जिनका अंततः कोई नतीजा नहीं निकलता।

पाकिस्तान 2021 से ही यह कहता आ रहा है कि अज़हर अब देश में नहीं है और अफ़गानिस्तान भाग गया है।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

'हैदराबाद मुक्ति दिवस' पर मुख्य अतिथि होंगे उपराष्ट्रपति

नईदिल्ली। केंद्र सरकार की ओर से 17 सितंबर को यहां आयोजित किए जाने वाले 'हैदराबाद मुक्ति दिवस' कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी. किशन रेड्डी ने मंगलवार को परेड ग्राउंड में कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी इस आयोजन में भाग लेंगे। यह आयोजन 1948 में निजाम शासन के तहत पूर्ववर्ती हैदराबाद रियासत के भारतीय संघ में (17 सितंबर को) विलय की वर्षगांठ मनाने के लिए आयोजित किया जाता है। रेड्डी ने तैयारियों का जायजा लेने के बाद संवाददाताओं से कहा कि यह आयोजन कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि तेलंगाना के चार करोड़ लोगों के स्वाभिमान का विषय है और निजाम शासन के खिलाफ लड़ाई में अपने प्राण न्योछावर करने वालों के प्रति श्रद्धांजलि है।

समान नागरिक संहिता पर उमर अब्दुल्ला का भाजपा पर तंज

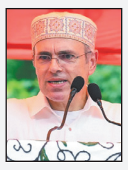

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पास समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक पारित कराने के लिए केंद्र में पर्याप्त संख्याबल है तो उसे इस विधेयक को अलग-अलग राज्यों के बजाय संसद में पेश करना चाहिए। अब्दुल्ला ने यहां संवाददाताओं से कहा, ''अगर आपके पास सांसदों की पर्याप्त संख्या है तो इसे संसद में पेश कीजिए। आप इसे अलग-अलग राज्यों के जरिए क्यों ला रहे हैं? वैसे भी उनके अपने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) में सभी यूसीसी पर सहमत नहीं हैं। खबरों के अनुसार, जनता दल (यूनाइटेड) ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि इसे बिहार में लागू नहीं किया जाएगा।'' अब्दुल्ला ने कहा कि भाजपा को यूसीसी को ''पिछले दरवाजे से'' नहीं लाना चाहिए। उन्होंने कहा, ''जिस तरह उनके अपने सहयोगी इसके पक्ष में नहीं हैं, मुझे नहीं लगता कि वे इसे संसद में पारित करा पाएंगे।

राहुल की मोहब्बत की दुकान सिर्फ भ्रष्टाचार का कारोबार

नईदिल्ली। भारतीय जनता पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी के खास नारे पर तंज कसते हुए कांग्रेस पर कई राज्यों में नौकरी चाहने वाले युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। मीडिया से बात करते हुए, स्वराज ने कांग्रेस पार्टी की मौजूदा या पिछली सरकारों वाले राज्यों में भर्ती में कथित गड़बड़ियों और प्रवर्तन की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस नेतृत्व पर निशाना साधा। बांसुरी स्वराज ने कहा कि ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तथाकथित मोहब्बत की दुकान सिर्फ़ भ्रष्टाचार का कारोबार करती है। स्वराज ने विपक्षी पार्टी के भीतर व्यवस्थित भ्रष्टाचार और राजनीतिक संरक्षण के अपने आरोपों को साबित करने के लिए तीन खास मामलों का ज़िक्र किया: उत्तराखंड वीपीडीओ परीक्षा घोटाला, छत्तीसगढ़ सीजीपीएससी पेपर लीक और हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स भर्ती।

यूएस दबाव में झुकी सरकार महंगे होंगे यूपीआई पेमेंट: राहुल

नईदिल्ली। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को केंद्र सरकार पर ज़्यादा कीमत वाले यूपीआई ट्रांज़ैक्शन पर शुल्क लगाने का रास्ता साफ़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस कदम से आगे चलकर ग्राहकों के लिए डिजिटल पेमेंट महंगा हो सकता है। यूपीआई चार्ज पर सरकार के हालिया नोटिफिकेशन पर प्रतिक्रिया देते हुए, गांधी ने दावा किया कि सरकार ने 2,000 रुपए से ज़्यादा के मर्चेंट ट्रांज़ैक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लगाने का रास्ता चुपचाप खोल दिया है। गांधी ने कहा कि अब 2,000 से ज़्यादा के मर्चेंट यूपीआई ट्रांज़ैक्शन पर एमडीआर लगाया जा सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि भले ही ऐसे ट्रांज़ैक्शन कुल वॉल्यूम का एक छोटा हिस्सा हों, लेकिन यूपीआई के ट्रांज़ैक्शन वैल्यू में इनका हिस्सा बहुत बड़ा है। हालांकि, सरकार ने अभी तक एमडीआर रेट की घोषणा नहीं की है और न ही 2,000 रुपए से ज़्यादा के यूपीआई ट्रांज़ैक्शन पर कोई चार्ज लगाया है।

ठाकरे परिवार पर सीबीआई की एफआईआर पर भड़के राउत

मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने आरोप लगाया है कि दिशा सालियन मामले में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) की ओर से दर्ज एफआईआर, ठाकरे परिवार की छवि खराब करने की कोशिश है। पत्रकारों से बात करते हुए उद्धव सेना के सांसद ने कहा कि सालियन की मौत के मामले में आया नया मोड़ एक राजनीतिक साज़िश है। सेना (यूबीटी) नेता ने मीडिया से कहा कि जिस तरह से यह मामला कोर्ट पहुँचा और कोर्ट ने (मामला सीबीआई को सौंपने का) आदेश दिया, वह एक साज़िश है। आदेश में खास तौर पर सीबीआई जाँच की बात कही गई है, लेकिन किसी का नाम नहीं लिया गया है। फिर भी मीडिया में नाम लिए जा रहे हैं। यह प्रतिक्रिया तब आई है जब सीबीआई ने दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर सालियन की मौत के मामले में एफआईआर दर्ज की है। उनके पिता की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, एफआईआर में किसी भी आरोपी का नाम नहीं है।

ब्रिक्स सम्मेलन से गया शांति का संदेश, कश्मीरी नेता भी खुश

कश्मीर के मीरवाइज उमर फारूक ने नयी दिल्ली में हाल में संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मंगलवार को तारीफ की और कहा कि इसने शांति एवं कूटनीति का अच्छा संदेश दिया। हालांकि, उन्होंने आगाह किया कि मौजूदा समय के युद्ध का दौर नहीं होने के दावे के बावजूद दुनियाभर में टकराव तेजी से बढ़ रहे हैं। जम्मू-कश्मीर के विभिन्न धार्मिक संगठनों के समूह 'मुत्ताहिदा मजलिस-ए-उलेमा' (एमएमयू) की बैठक के बाद संवाददाताओं से मुखातिब मीरवाइज ने उम्मीद जताई कि तनाव कम करने की कोशिशें रंग लाएंगी और पश्चिम एशिया में शांति बहाल होगी।

पूर्व अलगाववादी नेता ने दुनियाभर में बढ़ती हिंसा के बारे में जागरूकता बढ़ाने का अपना संकल्प दोहराया। उन्होंने कहा कि भले ही कई लोग कहते हों कि यह दौर युद्ध का दौर नहीं है, लेकिन दक्षिण एशिया और यूरोप से लेकर यूक्रेन और सूडान तक की जमीनी हकीकत लगातार बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और व्यापक उथल-पुथल पर प्रकाश डालती है। मीरवाइज ने पश्चिम एशिया, दक्षिण और मध्य एशिया, यूरोप, यूक्रेन तथा सूडान में बढ़ती अशांति का जिक्र करते हुए कहा, हमारी हमेशा यही कोशिश रही है कि जब भी मौका मिले, हम इस बात पर चर्चा करें कि दुनिया आज कैसी स्थिति का सामना कर रही है, जहां दुर्भाग्य से युद्ध दिन-ब-दिन बढ़ते जा रहे हैं।

हालांकि, हम कहते हैं कि यह दौर युद्ध का दौर नहीं है, लेकिन हमारे सामने जो हकीकत है, वह बिल्कुल इसके उलट है। भारत की अध्यक्षता में हाल में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बारे में मीरवाइज ने कहा, मैं समझता हूं कि यह भी एक अहम बात थी कि ब्रिक्स के सिलसिले में दुनियाभर के नेता दिल्ली में जमा हुए। वहां से शांति और कूटनीति का एक अच्छा संदेश गया। हमें उम्मीद है कि ये कोशिशें रंग लाएंगी और शांति कायम होगी... हम हमेशा से इसके समर्थक रहे हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और विदेश मंत्री अब्बास अराघची के साथ अपनी बातचीत से जुड़े एक सवाल के जवाब में मीरवाइज ने कहा कि मुलाकात अच्छी रही और इससे जम्मू-कश्मीर के लोगों की ओर से एकजुटता का संदेश पहुंचाने का मौका मिला। प्रवासीनेटवर्क जुड़ें उन्होंने कहा, हमने उन्हें एकजुटता का संदेश दिया। हमारा मानना ??है कि जब तक न्याय नहीं होता, तब तक शांति कायम नहीं हो सकती। इसलिए हमने उन्हें यह संदेश पहुंचाया। हमने ईरान और कश्मीर के बीच सदियों से मौजूद ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सभ्यतागत संबंधों के बारे में भी बात की। मीरवाइज ने कहा कि ईरानी नेताओं ने कश्मीर का दौरा करने और वहां के लोगों से बातचीत करने की गहरी इच्छा जाहिर की। मीरवाइज ने अराघची को पेजेश्कियान के नाम दो पन्ने का पत्र सौंपा, जिसमें उन्होंने संयम, बातचीत और कूटनीति का रास्ता अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी की 'अहिंसा' की विचारधारा की विरासत के साथ भारत बातचीत को बढ़ावा देने और पश्चिम एशिया के संघर्ष को और बढ़ने से रोकने में रचनात्मक भूमिका निभा सकता है।

एक नहीं, दिए गए थे दो निमंत्रणः तारिक अनवर

भारत ने मंगलवार को कहा कि बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक़ रहमान को दो अलग-अलग निमंत्रण मिले थे - एक द्विपक्षीय यात्रा के लिए और दूसरा बिम्सटेक के अध्यक्ष के तौर पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह स्पष्टीकरण तब दिया, जब ढाका ने कहा कि ब्रिक्स का निमंत्रण बांग्लादेश को बिम्सटेक अध्यक्ष के तौर पर दिया गया था, न कि रहमान को प्रधानमंत्री के तौर पर। जयसवाल ने एएनआई के एक सवाल के जवाब में कहा, हमने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को द्विपक्षीय यात्रा के लिए आमंत्रित किया था। इसके बाद, उन्हें बिम्सटेक के अध्यक्ष के तौर पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए भी आमंत्रित किया गया था। इसलिए, उन्हें दो निमंत्रण मिले थे। हाल ही में हुए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रहमान शामिल नहीं हुए, जबकि बांग्लादेश अभी बिम्सटेक की अध्यक्षता कर रहा है; बिम्सटेक बंगाल की खाड़ी के आस-पास स्थित सात देशों का एक बहुपक्षीय संगठन है।

> 31 मार्च 2026 को छत्तीसगढ़ ने एक ऐतिहासिक अध्याय लिखा। दशकों तक विकास में सबसे बड़ी बाधा रहे नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक सफलता ने राज्य को नई दिशा दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के नेतृत्व में लिया गया संकल्प आज ज़मीन पर साकार होता दिख रहा है। अब मई 2026 में पूरा छत्तीसगढ़ बदलाव की नई तस्वीर देख रहा है। वर्षों से उपेक्षित रहे बस्तर और दण्डकारण्य क्षेत्र तेज़ी से विकास, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य और रोजगार के नए दौर में आगे बढ़ रहे हैं। राज्य की 3 करोड़ जनता की ओर से इस ऐतिहासिक परिवर्तन के लिए केंद्र सरकार का आभार।
>
> — विष्णु देव साय,
> मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

बस्तर में लौटी शांति

चार दशकों के नक्सल दौर का अंत, विकास के नए युग की शुरुआत

लंबे समय तक नक्सलवाद की पहचान के साथ जिया बस्तर अब शांति और प्रगति की एक नई सुबह का साक्षी बन गया है। सुरक्षाबलों के कड़े संकल्प, सरकार की ठोस नीतियों और जनता के सहयोग से बस्तर के साथ ही पूरे देश से नक्सलवाद का अंत हो गया है। यह बंदूकों के शांत होने का समय नहीं, बल्कि असली बस्तर के उभरने का वक्त है।

सुरक्षा का मजबूत कवच

अबूझमाड जैसे दुर्गम इलाकों में सुरक्षा कैंप और ऑपरेशन से नक्सलियों के गढ़ ध्वस्त हुए। 2019 से अब तक 320 से ज्यादा नए कैंप स्थापित किए गए।

नक्सल मोर्चे पर कैसे मिली कामयाबी

छत्तीसगढ़ में लाल आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार ने बस्तर में करीब 24,000 कर्मियों की तैनाती की, जिसमें जिला रिजर्व गार्ड (डीआरजी), बस्तर फाइटर्स, स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और सीआरपीएफ शामिल हैं. इन सभी ने पहले दुर्गम इलाकों में एफओबी यानी फार्वर्ड बेस कैंप स्थापित किया. साल 2019 और 2025 के बीच 320 से ज्यादा नए शिविर स्थापित किए गए, जिससे सुरक्षा बलों को उन नक्सली गढ़ों में सुरक्षा की कमी की भरपाई का अवसर मिला, जहां पहले जाना असंभव था, जिनमें अबूझमाड़ क्षेत्र भी शामिल है।

विकास की नई रोशनी

सड़कें, स्कूल, अस्पताल, राशन की दुकान, आधार और राशन कार्ड हर गांव तक पहुंच रहे हैं। जहां कभी बंदूकें थी, वहां अब विकास की किरणें बस्तर के अंतिम छोर तक चमक रही है।

ऑपरेशन से मिला निर्णायक सफलता

- ऑपरेशन प्रहार (2017), ऑपरेशन कगार (2024) और ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट (2025) जैसे बड़े अभियानों ने नक्सलियों के नेटवर्क और नेतृत्व को कमजोर किया।
- ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट (21 अप्रैल-11 मई 2025) में 24 प्लस नक्सली ढेर, 54 गिरफ्तार और 84 आत्मसमर्पण हुए।
- कुरांकुदा और अबूझमाड़ में संयुक्त ऑपरेशन में कई शीर्ष नक्सली मारे गए, जिसमें शीर्ष नेता केशव राव भी शामिल है।

जो जवान ठान लेते हैं, वो करके दिखाते हैं

जवानों के शौर्य का स्वर्णिम अध्याय

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने सुरक्षा बलों, कोबरा टीम, बीएसएफ, छत्तीसगढ़ पुलिस और डीआरजी के साहस, बलिदान और समर्पण की सराहना करते हुए कहा कि 'जवान जो तय करते हैं, वो हासिल करते हैं।' शाह ने कहा कि सुरक्षा बलों ने माओवादियों के अड्डों को तहस-नहस कर विश्व को चौंका दिया है। उन्होंने बताया कि नक्सलवाद ने पिछले 35 वर्षों में हजारों लोगों की जान ली और आदिवासी क्षेत्रों को विकास से वंचित रखा। अब सरकार प्रभावित क्षेत्रों में अनाज, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, घर और शुद्ध पेयजल जैसी सुविधाएं पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि जब आदिवासी बच्चा बंदूक छोड़ पेंसिल पकड़ता है, तभी देश का भविष्य मजबूत होता है।

नक्सलियों की कमर तोड़ने वाले फैसले

- माओवादियों के वित्तीय नेटवर्क पर करारा प्रहार, संपत्तियों की जब्ती, संदिग्ध खनन व ठेकों पर रोक।
- नोटबंदी और डिजिटल भुगतान से नकदी की अर्थव्यवस्था कमजोर हुई।
- एनआईए, ईडी और राज्य पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से शेल कंपनियों, एनजीओ और अर्बन नक्सलियों पर बड़ी कार्रवाई।

- हर गांव में स्कूल
- हर गांव में राशन की दुकान
- हर तहसील में PHC, CHC
- गैस के चूल्हे और आवास
- रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के अवसर
- जनजातीय संस्कृति और परंपराओं का सम्मान

हिड़मा के आतंक का अंत, बस्तर में लौट रहा शांति का वसंत

छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए माडवी हिड़मा को ढेर कर बस्तर में शांति और विकास की दिशा मजबूत की है। मुख्यमंत्री श्री साय ने इसे निर्णायक उपलब्धि बताते हुए कहा कि केंद्र-राज्य की संयुक्त रणनीति से बस्तर में विश्वास, सुरक्षा और विकास का नया दौर शुरू हुआ है।

पापाराव का आत्मसमर्पण बना साय सरकार की बड़ी सफलता

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय सरकार की प्रभावी रणनीति, पुनर्वास नीति और सुरक्षा अभियान के चलते बस्तर में नक्सलवाद तेजी से कमजोर हुआ है। पापाराव सहित 18 माओवादियों का आत्मसमर्पण शांति, विकास और जनविश्वास की बड़ी जीत है। अब बस्तर नक्सलमुक्त भविष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

संवाद-48873/2

सुरक्षित बस्तर – समृद्ध बस्तर – विकसित बस्तर

पीएम आवास पर खुली बहस, भूपेश बघेल-विजय शर्मा आमने-सामने

रायपुर। पीएम आवास योजना को लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत एक बार फिर गरमा चुकी है। रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और डिप्टी सीएम सह गृहमंत्री विजय शर्मा आमने-सामने नजर आए। रायपुर प्रेस क्लब में पीएम आवास के मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस हुई। दोनों नेताओं ने अपने-अपने कार्यकाल में स्वीकृत और पूर्ण हुए आवासों के आंकड़े पेश किए।

बहस का असर प्रेस क्लब के बाहर भी देखने को मिला, जहां कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए, और एक-दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थिति को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया।

दरअसल, पीएम आवास के मुद्दे को लेकर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को खुली बहस की चुनौती दी थी। भूपेश बघेल ने इस चुनौती को स्वीकार किया। इसी के तहत दोनों नेता रायपुर प्रेस क्लब में आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पीएम आवास को लेकर दोनों पक्षों ने अपना-अपना पक्ष रखा। मामला केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रहा, दोनों नेताओं के बीच कई मौकों पर तीखी नोकझोंक भी हुई।

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने आंकड़े पेश करते हुए कहा, केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ में 17 लाख 75 हजार पीएम आवास पूर्ण किए। उन्होंने दावा किया कि भारत सरकार की वेबसाइट पर इसके पूरे आंकड़े उपलब्ध हैं। विजय शर्मा ने कहा कि 2025-26 में छत्तीसगढ़ ने देश में सर्वाधिक पीएम आवास बनाए हैं। विजय शर्मा ने पिछली कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उसके कार्यकाल में वित्तीय स्वीकृति तो हुई, लेकिन आवास पूर्ण नहीं हुए। विजय शर्मा के मुताबिक, कांग्रेस सरकार के पांच साल के कार्यकाल में आवास के लिए करीब 3,900 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति थी और करीब 3 लाख आवास पूर्ण हुए। वहीं भाजपा सरकार ने करीब ढाई साल में 16 हजार करोड़ रुपये खर्च किए।

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी अपने कार्यकाल के आंकड़े सामने रखे। बघेल ने कहा, 2018 में 3 लाख 48 हजार 960 घर स्वीकृत हुए थे, जिनमें से 1 लाख 39 हजार मकान पूर्ण हुए। 2020-21 वित्तीय वर्ष में 1 लाख 97 हजार 811 आवास का लक्ष्य था, जिसमें से 1 लाख 22 हजार आवास पूरे किए गए। भूपेश बघेल ने कहा कि कोरोना काल में किसी भी सरकार के पास पर्याप्त पैसा नहीं था। उन्होंने दावा किया कि 2022-23 में पीएम आवास का पोर्टल बंद कर दिया गया था और उनकी सरकार ने केंद्र सरकार से अपना पैसा मांगा था। इसके लिए केंद्र को लगातार पत्राचार भी किया गया। भूपेश बघेल के मुताबिक, 2011 की जनगणना के आधार पर करीब 18 लाख आवास बाकी थे, जिनमें से उनकी सरकार ने 6 लाख 97 हजार आवास स्वीकृत किए गए।

सियासी बहस के बीच पीएम आवास पोर्टल को लेकर दोनों नेताओं के बीच सबसे ज्यादा तीखी बहस देखने को मिली। भूपेश बघेल ने दावा किया कि 2022-23 में केंद्र सरकार ने पीएम आवास का पोर्टल बंद कर दिया था, जिसकी वजह से आवास योजना प्रभावित हुई। इसके जवाब में विजय शर्मा ने कहा कि पोर्टल बंद नहीं था और कोरोना के समय भी केंद्र से राशि आ रही थी।

विजय शर्मा ने आरोप लगाया कि मुद्दा पोर्टल का नहीं था, बल्कि तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह कहा था कि अगर यह प्रधानमंत्री आवास है तो प्रधानमंत्री ही जानें। उन्होंने कहा कि उस समय राज्य सरकार ने पूरी राशि अपनी तरफ से देने की बात कही थी। भूपेश बघेल ने अपने दावे पर कायम रहते हुए कहा कि पोर्टल बंद था। उन्होंने कहा कि सही क्या है, यह पत्रकार खुद जांच कर तय कर सकते हैं कि कौन सच बोल रहा है।

बहस के दौरान विजय शर्मा ने भूपेश बघेल के दावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके मंत्री रहे टीएस सिंहदेव ने राशि नहीं मिलने की वजह से पीएम आवास नहीं बन पाने का हवाला देते हुए इस्तीफा देने की बात कही थी। विजय शर्मा ने कहा कि कोरोना काल में भी केंद्र से राशि आ रही थी और पोर्टल बंद होने की बात सही नहीं है। इसी दौरान उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि ग्रोक से पूछिए, सच बताएगा।

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा, राज्य सरकार आवास बनाने का संकल्प लेती है और केंद्र सरकार से आवास का लोकेशन अप्रूव होता है। उन्होंने 2024-25 के आंकड़े सामने रखते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने 10 लाख 42 हजार 797 आवास दिए, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार ने 10 लाख 26 हजार 586 आवास लिए। विजय शर्मा ने कहा कि लोगों को बरगलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र में फिर भाजपा की सरकार बनी और 2 करोड़ आवास बनाने का संकल्प लिया गया, जिसके लिए केंद्र सरकार ने किस्त भी जारी की। उन्होंने कहा कि वे यहां राजनीति करने नहीं, बल्कि आंकड़ों की चर्चा करने आए हैं और अगर कहीं कोई कमी है तो उसे मिलकर ठीक किया जा सकता है।

भूपेश बघेल ने कोरोना काल का हवाला देते हुए कहा कि उस दौरान किसी भी राज्य के पास पर्याप्त पैसा नहीं था। उन्होंने दावा किया कि उनकी सरकार ने आवास बनाने के लिए आरबीआई से लोन लिया था। भूपेश बघेल ने कहा कि उस समय सरकार वेतन तक देने की स्थिति में नहीं थी। उन्होंने फिर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने पीएम आवास का पोर्टल बंद कर दिया था। उन्होंने भाजपा सरकार के 18 लाख पीएम आवास स्वीकृत करने के दावे पर भी सवाल उठाया। बघेल ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान अब तक 10 लाख पीएम आवास की स्वीकृति कर चुके हैं। सरकार के अनुसार यह आंकड़ा आगे बढ़कर 46 लाख तक पहुंच गया है।

बहस के दौरान दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप भी लगे। भूपेश बघेल ने विजय शर्मा से कहा कि वे यह कहना बंद करें कि 18 लाख आवास बनाए गए हैं। इसके जवाब में विजय शर्मा ने कहा कि भूपेश बघेल को यह कहना बंद करना चाहिए कि केंद्र ने राशि स्वीकार नहीं की थी। विजय शर्मा ने आरोप लगाया कि तत्कालीन सरकार ने जानबूझकर पोर्टल पर जानकारी नहीं डाली और बाद में केंद्र सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने यहां तक कहा कि आपने गरीबों की आह ली, इसलिए सरकार गई।

डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि उन्होंने पूरी रिपोर्ट और आंकड़ों के साथ अपनी बात रखी है, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है।उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में करीब 3 लाख आवास बनाए गए, जबकि छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने 18 लाख पीएम आवास बनाने का संकल्प लिया है। विजय शर्मा ने भूपेश बघेल पर गरीबों के आवास रोकने का आरोप लगाते हुए कहा कि जांच में यह सामने आता है कि कई लोग मकान मिलने का इंतजार करते-करते दुनिया से चले गए।

भूपेश बघेल ने अपने पक्ष में एक और आंकड़ा रखते हुए कहा कि 25 सितंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक 18 लाख मकान स्वीकृत किए गए। उन्होंने कहा कि पीएम आवास को लेकर अलग-अलग आंकड़े सामने आ रहे हैं और इस पूरे मामले में वास्तविक स्थिति आंकड़ों की जांच के बाद ही स्पष्ट होगी। वहीं विजय शर्मा लगातार इस बात पर जोर देते रहे कि केंद्र सरकार की वेबसाइट पर पीएम आवास से जुड़े पूरे आंकड़े उपलब्ध हैं और कांग्रेस को तथ्यों के साथ बात करनी चाहिए।

कुल मिलाकर पीएम आवास का मुद्दा एक बार फिर छत्तीसगढ़ की राजनीति के केंद्र में आ गया है। एक तरफ भाजपा सरकार अपने कार्यकाल में बड़ी संख्या में पीएम आवास पूरे करने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपने शासनकाल में स्वीकृत आवासों और केंद्र से राशि व पोर्टल को लेकर किए गए लेटर का हवाला दे रही है। रायपुर प्रेस क्लब में हुई आमने-सामने की बहस ने साफ कर दिया कि पीएम आवास के आंकड़ों की लड़ाई अब सियासी आरोप-प्रत्यारोप का बड़ा मुद्दा बन चुकी है।

प्रेस क्लब के बाहर भी सियासी गर्मी बढ़ी

रायपुर प्रेस क्लब के अंदर जहां दोनों नेताओं के बीच पीएम आवास के आंकड़ों को लेकर बहस चल रही थी, वहीं इसकी गर्माहट बाहर भी देखने को मिली। कार्यक्रम के दौरान धीरे-धीरे कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता प्रेस क्लब के बाहर जमा होने लगे। भीड़ बढ़ने के साथ दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं ने एक-दूसरे के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम आवास नहीं दिए जाने का आरोप लगाते हुए सरकार के खिलाफ नारे लगाए। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए अपने कार्यकाल में बड़ी संख्या में पीएम आवास दिए जाने का दावा किया।

कार्यकर्ताओं के आमने-सामने आने और नारेबाजी को देखते हुए प्रेस क्लब के अंदर और बाहर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। मौके पर कई पुलिस अधिकारी भी मौजूद रहे और स्थिति पर नजर रखी गई। कार्यक्रम के दौरान अंदर नेताओं के बीच आंकड़ों की सियासी लड़ाई चलती रही, तो बाहर दोनों दलों के कार्यकर्ताओं के बीच नारेबाजी से माहौल गरमाता रहा।

संक्षिप्त समाचार

नुआखाई समृद्ध कृषि परंपरा, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और अन्नदाता के परिश्रम का उत्सव

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने नई फसल के स्वागत और प्रकृति के अनुपम उपहार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने वाले पावन पर्व नुआखाई के अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अन्नदाता किसानों की सुख-समृद्धि, अच्छी फसल और सभी परिवारों की खुशहाली की मंगलकामना की है। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि नुआखाई समृद्ध कृषि संस्कृति और लोक परंपराओं से जुड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। नई फसल के आगमन की खुशी में मनाया जाने वाला यह पर्व प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, अन्न के सम्मान और किसान के अथक परिश्रम के प्रति आदर का भाव प्रकट करता है। खेतों में उपजी नई फसल केवल किसान की मेहनत का प्रतिफल नहीं, बल्कि प्रकृति की कृपा और हमारी कृषि प्रधान संस्कृति की समृद्धि का भी प्रतीक है। मुख्यमंत्री श्री साय ने नुआखाई के पावन अवसर पर कामना करते हुए कहा कि प्रकृति की कृपा छत्तीसगढ़ पर सदैव बनी रहे। हमारे किसान साथियों के खेत हरे-भरे और फसलों से लहलहाते रहें, अन्न के भंडार भरें तथा अन्नदाताओं के घर-आंगन में समृद्धि आए। प्रदेश के प्रत्येक परिवार के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली का संचार हो तथा आपसी प्रेम, भाईचारा और सद्भाव निरंतर मजबूत होता रहे।

मंत्री टंक राम वर्मा ने माटी के दीप खरीदकर दिया 'जनभागीदारी' का संदेश

रायपुर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के आगामी

17 सितंबर को जन्मदिवस और सार्वजनिक जीवन में 25 वर्षों के निरंतर सेवाकाल पूर्ण होने के पावन अवसर पर प्रदेशभर में उत्साह का माहौल है। इस अवसर को खास बनाने और प्रधानमंत्री के स्वस्थ, दीर्घायु एवं यशस्वी जीवन की कामना के लिए राजस्व एवं जिला प्रभारी मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने प्रदेशवासियों से 17 सितंबर की संध्या अपने घरों, प्रतिष्ठानों एवं सार्वजनिक स्थलों पर दीप प्रज्ज्वलित करने की अपील की है। माटी के शिल्पकारों को संबल देने और 'जनभागीदारी' का संदेश प्रसारित करने के उद्देश्य से मंत्री श्री वर्मा ने बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के तिल्दा क्षेत्र स्थित मोहभट्ठा पारा पहुंचकर स्थानीय कुम्हारों से स्वयं मिट्टी के दीप खरीदे। इस दौरान उन्होंने वोकल फॉर लोकल के भाव को आत्मसात करते हुए स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहित किया। मंत्री श्री टंकराम वर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने सार्वजनिक जीवन में राष्ट्रसेवा, जनकल्याण और अंतिम व्यक्ति के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उनके 25 वर्षों का सेवाकाल त्याग, निष्ठा और दृढ़ संकल्प का उदाहरण है। उनके जन्मदिवस को सेवा और समर्पण के साथ मनाना हम सभी के लिए गर्व और प्रेरणा का विषय है। उन्होंने नागरिकों से आग्रह किया कि 17 सितंबर को हर परिवार कम से कम एक मिट्टी का दीपक जलाकर प्रधानमंत्री मोदी के प्रति आभार व्यक्त करे और इस जनभागीदारी अभियान का हिस्सा बने।

रायपुर में नियमों की खुलेआम उड़ रही धज्जियां : कागजों में 'नो फ्लैक्स जोन'

रायपुर। राजधानी रायपुर की सड़कों पर नगर निगम के नियमों की खुलेआम अनदेखी होती नजर आ रही है। शहर में जगह-जगह बिजली के खंभों, बिल्डिंगों और सड़क किनारे रंग-बिरंगे फ्लैक्स-बैनर लटके हुए हैं। इनमें राजनीतिक नेताओं के जन्मदिन और बधाई संदेश से लेकर व्यावसायिक विज्ञापन और सरकारी कार्यक्रमों के प्रचार तक शामिल हैं। खास बात यह है कि इनमें से कई पोस्टर-बैनर उन मार्गों पर भी लगे हैं, जिन्हें नगर निगम ने 'नो फ्लैक्स जोन' घोषित कर रखा है। इन लटकते फ्लैक्स से जहां शहर की सुंदरता प्रभावित हो रही है, वहीं हवा और बारिश के दौरान इनके गिरने का खतरा भी बना रहता है। सड़क के बीच या किनारे लगाए गए बड़े-बड़े बैनर कई जगह वाहन चालकों की विजिबिलिटी भी प्रभावित कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि नियमों के बावजूद इन पर प्रभावी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? नगर निगम ने आउटडोर एडवरटाइजमेंट पॉलिसी के तहत बिना अनुमति, शुल्क या निर्धारित मापदंडों के विपरीत पोस्टर-बैनर लगाने पर जुर्माने का प्रावधान किया है। शहर के 10 जोनों में पोस्टर-बैनर लगाने के लिए निर्धारित स्थल भी चिन्हित किए गए हैं। इसके अलावा छह प्रमुख मार्गों को नो फ्लैक्स जोन घोषित किया गया है। इनमें महिला थाना से बूढ़ेश्वर मंदिर, तेलीबांधा थाना चौक से टाटीबंध, कोतवाली से जयस्तंभ चौक, सिविल लाइन और पचपेड़ी नाका से लालपुर ओवरब्रिज तक के प्रमुख मार्ग शामिल हैं।

हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: सेवानिवृत्ति के अंतिम वर्ष में गृह जिले में मिलेगी पोस्टिंग

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने एक मामले में आदेश दिया है कि रिटायरमेंट के आखिरी वर्ष में कर्मचारी को गृह जिले में नियुक्ति देनी चाहिए। आबकारी विभाग के हेड कांस्टेबल की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनको गृह जिले बिलासपुर में पदस्थ करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने संबंधित अधिकारी को आदेश की प्रति मिलने के 15 दिनों के भीतर आवश्यक पोस्टिंग के आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं। याचिकाकर्ता हेड कांस्टेबल अभी रायगढ़ जिले में पदस्थ हैं। उन्होंने रिटायरमेंट करीब होने के कारण रायगढ़ से बिलासपुर तबादले की मांग की थी। याचिका में वर्ष 2025 की ट्रांसफर पॉलिसी के क्लॉज 3.12 का लाभ देने की मांग करते हुए याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उनकी नियुक्ति 19 अप्रैल 1993 को आबकारी विभाग में सेल्समैन के रूप में हुई थी।

महाराजा चक्रधर सिंह की विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचा रहा चक्रधर समारोह : राज्यपाल

- **23 सितम्बर तक रामलीला मैदान में देश-प्रदेश के कलाकार देंगे प्रस्तुतियां**

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने संगीत, नृत्य और कला की समृद्ध परंपरा से जुड़ी रायगढ़ की धरती पर 41वें अंतर्राष्ट्रीय चक्रधर समारोह का सोमवार को महाराजा चक्रधर की तैलचित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलित कर विधिवत भव्य शुभारंभ किया। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने समारोह का शुभारंभ करते हुए कहा कि यह आयोजन केवल कला प्रस्तुतियों का मंच नहीं, बल्कि महाराजा चक्रधर सिंह की कला-साधना और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। 14 से 23 सितम्बर तक रामलीला मैदान में आयोजित समारोह में देश-प्रदेश के ख्यातिप्राप्त कलाकारों के साथ स्थानीय प्रतिभाएं भी गायन, वादन, नृत्य और लोककला की प्रस्तुतियां देंगी।

शुभारंभ अवसर पर राज्यपाल श्री रमेन डेका ने समारोह में प्रस्तुति देने वाले कलाकारों का सम्मान किया। पद्मश्री डॉ. उषा बारले, पद्मश्री श्री अनुज शर्मा सहित अन्य कलाकारों और कला गुरु स्वर्गीय वेदमणि सिंह ठाकुर के शिष्यों ने प्रस्तुतियां दीं। कलाकारों की प्रस्तुतियों ने समारोह की सांस्कृतिक गरिमा को और ऊंचाई प्रदान की। राज्यपाल श्री रमेन डेका ने कहा कि चक्रधर समारोह महाराजा चक्रधर सिंह की कला साधना और उनकी दूरदृष्टि को स्मरण करने का अवसर है। रायगढ़ भारतीय शास्त्रीय कलाओं की महत्वपूर्ण धरोहर भूमि है और रायगढ़ घराने के कथक ने देश ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है। महाराजा चक्रधर सिंह ने राजसिंहासन से अधिक महत्व कला को दिया। उन्होंने कलाकारों को संरक्षण दिया और संगीत, नृत्य एवं साहित्य को आमजन के जीवन से जोडऩे का कार्य किया। उन्होंने कहा कि महाराजा चक्रधर सिंह की कृतियां नर्तन सर्वस्व, तालतोय निधि और राग रत्न मंजूषा आज भी कला और साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण धरोहर हैं। उन्होंने अपनी साधना से यह सिद्ध किया कि कला किसी एक स्थान या केंद्र की मोहताज नहीं होती। जहां निरंतर साधना होती है, वही स्थान कला का तीर्थ बन जाता है। रायगढ़ की पहचान आज संगीत, घुंघरुओं की झंकार, तबले की थाप और नृत्य की भाव-भंगिमाओं से जुड़ी है।

राज्यपाल ने कहा कि चक्रधर समारोह अब केवल एक शासकीय या संस्थागत आयोजन नहीं रहा, बल्कि यह रायगढ़ की सांस्कृतिक धड़कन बन चुका है। देश के प्रतिष्ठित कलाकारों के साथ स्थानीय प्रतिभाओं को मंच मिलना इस समारोह की विशेषता है। ऐसे आयोजन नई पीढ़ी में अपनी जड़ों के प्रति जुड़ाव पैदा करते हैं। युवाओं को परंपरा के साथ नवाचार को जोड़ते हुए कला को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने छत्तीसगढ़ की समृद्ध लोक परंपराओं का उल्लेख करते हुए कहा कि पंथी, राउत नाचा, भरथरी, सुआ, करमा सहित आदिवासी नृत्य और लोकगीत हमारी सांस्कृतिक विविधता की पहचान हैं। भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी विविधता में एकता है और चक्रधर समारोह इसी सांस्कृतिक एकता का जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है।

हर गांव और हर नागरिक तक पहुंचे सेवा और सुशासन का संदेश: मंत्री बघेल

- **सेवा संकल्प अभियान की तैयारियों के संबंध में बैठक संपन्न**

रायपुर। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री सूरजपुर जिले के प्रभारी मंत्री दयालदास बघेल की अध्यक्षता में सेवा संकल्प अभियान के सफल संचालन को लेकर संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई। बैठक में महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, प्रेमनगर विधायक श्री भूलन सिंह मरावी, वन विकास निगम के अध्यक्ष श्री रामसेवक पैंकरा सहित जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी एवं विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

मंत्री श्री बघेल ने अभियान की तैयारियों की विस्तारपूर्वक समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जनभागीदारी के साथ सेवा संकल्प अभियान को जिले के प्रत्येक गांव, पंचायत , हर नागरिक तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों की सेवा के अवसर पर आयोजित

होने वाले इस अभियान को व्यापक स्वरूप देते हुए समाज के प्रत्येक वर्ग को इससे जोडऩा है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों एवं कर्मचारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।

उन्होंने कहा कि अभियान के तहत कहानी बदलाव की को जन-जन तक पहुंचाएं। लोगों को बताएं कि पहले परिस्थितियां कैसी थीं और आज विकास एवं जनकल्याण की दिशा में क्या बदलाव आया है।

उन्होंने कहा कि योजनाओं और विकास कार्यों का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना ही अभियान की सार्थकता है। मंत्री ने पंचायत स्तर तक शासन की योजनाओं एवं उपलब्धियों की जानकारी पहुंचाने के साथ ही आंगनबाड़ी केंद्रों में भी बेहतर एवं रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। आ ं ग न बा ड. ी कार्यकर्ताओं के सम्मान, स्वास्थ्य परीक्षण, सेवा सेतु अभियान सरकार, आपके द्वार सहित जनहित से जुड़े कार्यक्रमों को प्राथमिकता देने की बात कही। मंत्री श्री बघेल ने बैठक में 25 करोड़ बच्चों के सपनों का भारत,सेवा ज्योति यात्रा, सेवा मेरा योगदान सहित विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मंत्री श्री बघेल ने कहा कि सभी कार्यक्रमों को भव्य, गरिमामय एवं जनभागीदारीपूर्ण बनाएं, ताकि सेवा, सुशासन और राष्ट्र निर्माण का संदेश व्यापक स्तर पर पहुंचे।

उन्होंने पदाधिकारियों एवं अधिकारियों से कहा कि सभी आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए अभियान की गतिविधियों को सफल बनाएं। विकसित भारत के निर्माण में समाज के प्रत्येक व्यक्ति की सहभागिता आवश्यक है।

सड़क किनारे पसरे पर अचानक पहुंचे मुख्यमंत्री, मीरा के पसरे से खरीदा आशीर्वाद का दीया

मुख्यमंत्री ने पूछा - सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है? मीरा ने बताया - जनधन खाता खुला है, महतारी वंदन योजना की राशि भी मिल रही

रायपुर। राजधानी रायपुर के तेलीबांधा मरीन ड्राइव में सड़क किनारे पसरा लगाकर मिट्टी के दीये बेच रही मीरा के लिए आज का दिन अचानक बेहद खास बन गया। रोज की तरह वह अपने छोटे से पसरे पर दीये सजाकर ग्राहकों की प्रतीक्षा कर रही थी। इसी बीच मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय का काफिला अचानक उसके पसरे के पास जाकर रुक गया।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने मीरा के पसरे पर रखे मिट्टी के दीयों को देखा और सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित होने वाले आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम के लिए वहीं से एक दीया खरीदा। मुख्यमंत्री ने महिला को एक हजार रुपए प्रदान किए। मुख्यमंत्री का यह सहज भाव स्थानीय स्तर पर छोटे व्यवसाय के माध्यम से आजीविका अर्जित करने वाली मीरा के श्रम, स्वाभिमान और स्वावलंबन के सम्मान का सुंदर संदेश भी दे गया। मुख्यमंत्री का सड़क किनारे लगे छोटे से पसरे पर अचानक पहुंचना आसपास मौजूद लोगों के लिए भी सुखद आश्चर्य का अवसर बन गया। बिना किसी औपचारिकता के मुख्यमंत्री ने मीरा से उसके कामकाज और परिवार का हालचाल पूछा।

बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री श्री साय ने मीरा से पूछा कि उसे केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं। मुख्यमंत्री के सवाल पर मीरा ने बताया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत उसका बैंक खाता खुल चुका है। उसने मुख्यमंत्री को यह भी बताया कि राज्य सरकार की महतारी वंदन योजना के अंतर्गत उसे हर महीने एक हजार रुपए की राशि प्राप्त हो रही है। महिला के मुंह से योजनाओं का लाभ मिलने की बात सुनकर मुख्यमंत्री साय ने प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाएं तभी सार्थक होती हैं, जब उनका लाभ जरूरतमंद व्यक्ति तक सीधे पहुंचे, उसे संबल दे और उसके जीवन को बेहतर बनाने में सहायक बने। शासन की प्राथमिकता यही है कि जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पूरी सहजता और पारदर्शिता के साथ पहुंचे।

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री जनधन योजना ने गरीब, वंचित और जरूरतमंद परिवारों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़कर आर्थिक समावेशन का मजबूत आधार तैयार किया है। बैंकिंग व्यवस्था से जुडऩे के कारण आज विभिन्न योजनाओं की राशि सीधे हितग्राहियों के खातों तक पहुंच रही है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में महतारी

वंदन योजना के माध्यम से प्रदेश की माताओं-बहनों को प्रतिमाह एक हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। यह राशि उनके छोटे-बड़े दैनिक खर्चों में सहयोग देने के साथ उनमें आर्थिक आत्मविश्वास भी बढ़ा रही है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि सड़क किनारे पसरा लगाने वाले छोटे विक्रेता हों, कुम्हार हों, शिल्पकार हों अथवा स्थानीय उत्पाद तैयार करने वाली हमारी माताएं और बहनें - इन सभी के परिश्रम में आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ की शक्ति निहित है। अपने हुनर और मेहनत से आजीविका अर्जित करने वाले ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को अपनाना केवल किसी वस्तु की खरीद नहीं है। उसके पीछे किसी परिवार का श्रम, किसी कारीगर का हुनर और किसी छोटे व्यवसायी के आत्मसम्मान से जुड़ी आजीविका होती है। जब हम स्थानीय विक्रेताओं और कारीगरों से सामान खरीदते हैं तो हमारे इस छोटे से प्रयास से उनके परिवार और उनकी आजीविका को संबल मिलता है।

मुख्यमंत्री श्री साय द्वारा मीरा से खरीदा गया मिट्टी का यह दीया सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत आयोजित होने वाले आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम का हिस्सा बनेगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से सेवा, जनकल्याण और विकास के प्रति सामूहिक संकल्प को जनभागीदारी से जोडऩे का प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि हमारी संस्कृति में दीया केवल प्रकाश का माध्यम नहीं, बल्कि आशा और सकारात्मक संकल्प का प्रतीक है। मिट्टी का एक छोटा-सा दीया जब जलता है तो अपने आसपास के अंधकार को दूर करता है। इसी तरह समाज का प्रत्येक व्यक्ति जब सेवा का एक छोटा-सा संकल्प लेकर आगे बढ़ता है तो सामूहिक प्रयास से बड़े और सकारात्मक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त होता है। उन्होंने कहा कि आशीर्वाद का दीया इसी भावना को अभिव्यक्त करता है। यह सेवा और विकास के प्रति हमारे संकल्प तथा जनभागीदारी के सामर्थ्य का प्रतीक है। प्रदेश के नागरिक जब इस भावना से जुड़ेंगे तो सेवा का यह संकल्प घर-घर और जन-जन तक पहुंचेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष राष्ट्र और जनसेवा को समर्पित किए हैं। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान आयोजित किया जा रहा है। यह अभियान सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और विकास के प्रति प्रतिबद्धता को जनभागीदारी के माध्यम से और मजबूत करने का अवसर है। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे सेवा संकल्प अभियान से पूरे उत्साह और आत्मीयता के साथ जुड़ें। अपने गांव, शहर और आसपास स्वच्छता के कार्यों में सहभागी बनें, पर्यावरण संरक्षण के लिए आगे आएं, जरूरतमंदों की सहायता करें और अपनी क्षमता के अनुरूप जनसेवा का कोई न कोई संकल्प अवश्य लें। उन्होंने कहा कि सेवा का कोई कार्य छोटा नहीं होता। किसी जरूरतमंद की सहायता, अपने आसपास स्वच्छता, एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करना, स्थानीय कारीगर से कोई वस्तु खरीदना अथवा समाज के हित में किया गया छोटा-सा प्रयास भी जनसेवा का महत्वपूर्ण माध्यम बन सकता है।

ब्रिक्स में भारत की शानदार कूटनीतिक सफलता

नीरज कुमार दुबे

दिल्ली में हुई ब्रिक्स शिखर बैठक को अगर केवल एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन मानकर देखा जाएगा तो उसकी असली राजनीतिक अहमियत समझ में नहीं आएगी। देखा जाये तो यह बैठक ऐसे समय में हुई, जब दुनिया कई मोर्चों पर तनाव, युद्ध, अविश्वास और बदलते शक्ति-संतुलन से गुजर रही है। ऐसे माहौल में भारत ने जिस तरह अलग-अलग ध्रुवों के देशों को एक मंच पर बैठाया, संवाद के रास्ते खोले और मतभेदों के बावजूद सहयोग की जमीन तैयार की, वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति के लिए एक बड़ी कूटनीतिक उपलब्धि के तौर पर सामने आई है। ब्रिक्स की इस बैठक की सबसे बड़ी सफलता यही रही कि भारत ने उन देशों के बीच भी संवाद की संभावना पैदा की, जिनके बीच गहरे मतभेद हैं। ईरान और खाड़ी के देशों के बीच बातचीत इसका सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है। पश्चिम एशिया लंबे समय से टकराव, अविश्वास और संघर्ष का मैदान बना हुआ है। ऐसे समय में दिल्ली का मंच बातचीत के लिए उपलब्ध होना अपने आप में भारत की बढ़ती स्वीकार्यता का संकेत है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह दिखाया कि भारत किसी एक खेमे का हिस्सा बनकर नहीं, बल्कि अलग-अलग पक्षों से संवाद करते हुए अपने लिए स्वतंत्र कूटनीतिक स्थान बना सकता है। भारत और चीन के बीच हुई बातचीत भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। सीमा विवाद और लंबे समय से चले आ रहे तनाव के बावजूद दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व का आमने-सामने बैठना इस बात का प्रमाण है कि भारत अपनी राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से समझौता किए बिना संवाद के दरवाजे बंद नहीं करता। यही वह बिंदु है जहां मोदी की कूटनीति की ताकत दिखाई देती है। अमेरिका से संबंध भी कायम हैं, रूस के साथ रिश्ते भी बने हुए हैं, चीन से संवाद भी हो रहा है और पश्चिम एशिया के अलग-अलग देशों के साथ भारत की स्वीकार्यता लगातार बढ़ रही है। यानी भारत किसी एक शक्ति के पीछे चलने के बजाय अपनी शर्तों पर संबंधों का संतुलन साध रहा है। यही सफलता उस राजनीतिक नैरेटिव को भी कमजोर करती है, जिसमें बार-बार यह सवाल उठाया जाता रहा कि अगर पड़ोसी देश पाकिस्तान ने मक्का समझौता कर लिया, दूसरे देशों के साथ अपने समीकरण बना लिए और क्षेत्रीय स्तर पर भारत के खिलाफ गतिविधियां बढ़ीं तो क्या भारत की विदेश नीति असफल हो गई? विदेश नीति को केवल पड़ोस की तत्काल घटनाओं से मापना वास्तविक तस्वीर को छोटा कर देना है। असली सवाल यह है कि दुनिया की बड़ी शक्तियां भारत को किस नजर से देख रही हैं और संकट के समय कितने देश भारत के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। दिल्ली की बैठक ने इस सवाल का जवाब काफी हद तक दे दिया है। यहां प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत कूटनीतिक छवि भी महत्वपूर्ण हो जाती है। नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी चिनफिंग की तस्वीरें जिस तरह वैश्विक स्तर पर चर्चा में आई हैं, उनका राजनीतिक संदेश तस्वीर से कहीं बड़ा है। यह तस्वीर बताती है कि भारत का नेतृत्व एक साथ दुनिया की अलग-अलग शक्तियों के साथ संवाद करने की स्थिति में है। पश्चिमी देशों के लिए भी यह संदेश महत्वपूर्ण है कि भारत को नजरअंदाज करके वैश्विक राजनीति की कोई बड़ी रणनीति पूरी नहीं हो सकती। इसका घरेलू राजनीतिक असर भी कम नहीं होगा। भाजपा लंबे समय से प्रधानमंत्री मोदी की मजबूत वैश्विक छवि को अपनी राजनीतिक पूंजी के रूप में इस्तेमाल करती रही है। विपक्ष यदि यह कहता है कि सरकार की विदेश नीति कमजोर पड़ गई है, तो भाजपा के पास दिल्ली में जुटे वैश्विक नेताओं, भारत की मध्यस्थ भूमिका और अलग-अलग शक्ति केंद्रों के साथ संवाद को सामने रखने का मजबूत राजनीतिक आधार तैयार हो गया है।

ब्रिक्स में भारत की जय-जयकार और बदलती वैश्विक व्यवस्था

कांतिलाल मांडोत

नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन ने बदलती वैश्विक राजनीति में भारत की बढ़ती भूमिका का प्रभावशाली प्रदर्शन किया है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह आतंकवाद के खिलाफ स्पष्ट और कठोर रुख रखा, वैश्विक दक्षिण को निर्णय प्रक्रिया में अधिक प्रभावी भूमिका देने की बात कही और अलग-अलग मत रखने वाले देशों को एक साझा घोषणापत्र पर सहमत कराया, उससे भारत की कूटनीतिक क्षमता सामने आई है। सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि ब्रिक्स देशों ने आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहनशीलता की नीति पर सहमति जताई। पहलगाम आतंकी हमले की निंदा ने भारत के उस लंबे प्रयास को मजबूती दी है जिसमें वह आतंकवाद को किसी भी राजनीतिक या रणनीतिक बहाने से अलग रखकर उसके खिलाफ वैश्विक एकजुटता की मांग करता रहा है।

ब्रिक्स का दिल्ली घोषणापत्र इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस संगठन में ऐसे देश शामिल हैं जिनके बीच अनेक अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर गंभीर मतभेद हैं। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। पश्चिम एशिया में ईरान, इजरायल और अरब देशों के बीच तनाव की स्थिति बनी हुई है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ईरान जैसे देशों के अपने-अपने क्षेत्रीय हित हैं। ऐसे वातावरण में सभी सदस्य देशों को एक साझा दस्तावेज पर सहमत कराना आसान काम नहीं था। भारत ने किसी एक देश को कठघरे में खड़ा करने के बजाय आतंकवाद, युद्ध, आर्थिक दबाव और वैश्विक संस्थाओं में सुधार जैसे व्यापक मुद्दों पर सहमति बनाने का रास्ता चुना। यही भारतीय कूटनीति की सबसे बड़ी विशेषता रही।

घोषणापत्र में पहलगाम आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा और सीमा पार आतंकवाद सहित आतंकवाद के किसी भी रूप के खिलाफ शून्य सहनशीलता का संदेश भारत के लिए विशेष महत्व रखता है। आतंकवाद के वित्तपोषण और उसे संरक्षण देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत पर जोर देकर ब्रिक्स ने यह संकेत दिया है कि आतंकवाद केवल किसी एक देश की सुरक्षा समस्या नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए चुनौती है। यह भारत के लिए इसलिए भी बड़ी उपलब्धि है क्योंकि आतंकवाद के मुद्दे पर वैश्विक मंचों पर लंबे समय से वह अधिक स्पष्ट और प्रभावी अंतरराष्ट्रीय कार्रवाई की मांग करता रहा है। ब्रिक्स घोषणापत्र का एक और महत्वपूर्ण पक्ष संयुक्त राष्ट्र और उसकी प्रमुख संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता पर सहमति है। सुरक्षा परिषद में भारत और ब्राजील की बड़ी भूमिका का समर्थन वैश्विक शासन व्यवस्था में बदलाव की बढ़ती मांग को दर्शाता है। भारत लंबे समय से कहता रहा है कि वर्तमान वैश्विक संस्थाएं आज की दुनिया की वास्तविकताओं का पूरा प्रतिनिधित्व नहीं करतीं। जब विश्व की आर्थिक और जनसंख्या संबंधी तस्वीर बदल चुकी है, तब निर्णय लेने वाली संस्थाओं में भी इसका प्रतिबिंब दिखाई देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने इसी भावना को आगे बढ़ाते हुए कहा कि वैश्विक दक्षिण को केवल नियमों का पालन करने वाला नहीं बल्कि नियम तय करने वाला बनना होगा।

प्रधानमंत्री का यह संदेश ब्रिक्स की मूल भावना से भी जुड़ा हुआ है। भारत ने स्पष्ट किया कि ब्रिक्स किसी देश के खिलाफ बनाया गया मंच नहीं है। इसका उद्देश्य परस्पर सहयोग, विकास और वैश्विक समस्याओं के समाधान के लिए संवाद को बढ़ावा देना है। यह रुख ऐसे समय में महत्वपूर्ण है जब अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ व्यापार, शुल्क और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा को लेकर दुनिया में तनाव बढ़ा हुआ है। घोषणापत्र में एकतरफा आर्थिक प्रतिबंधों, मनमाने शुल्क और गैर-शुल्क बाधाओं का विरोध तथा विश्व व्यापार संगठन में सुधार की आवश्यकता पर जोर देकर ब्रिक्स देशों ने नियम आधारित और अधिक संतुलित वैश्विक व्यापार व्यवस्था की मांग रखी है।

आर्थिक क्षेत्र में स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ाने और सीमा पार भुगतान व्यवस्था को तेज तथा सरल बनाने पर जोर भी भविष्य की दिशा का संकेत देता है। इसका उद्देश्य डॉलर आधारित व्यवस्था को तत्काल समाप्त करना नहीं बल्कि देशों के बीच व्यापार के लिए अधिक विकल्प तैयार करना है। यदि ब्रिक्स देश स्थानीय मुद्राओं में व्यापार और भुगतान की व्यवस्था को मजबूत करते हैं तो इससे आपसी आर्थिक निर्भरता बढ़ सकती है और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में नई व्यवस्थाओं को गति मिल सकती है। ऊर्जा सुरक्षा को लेकर भी सम्मेलन में महत्वपूर्ण चर्चा हुई। ऊर्जा का निर्बाध प्रवाह, महत्वपूर्ण ऊर्जा ढांचे की सुरक्षा और मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं पर जोर पश्चिम एशिया के तनाव की पृष्ठभूमि में विशेष महत्व रखता है।

फिलिस्तीन के मुद्दे पर दो-राष्ट्र समाधान और संयुक्त राष्ट्र में फिलिस्तीन की पूर्ण सदस्यता के समर्थन से ब्रिक्स ने पश्चिम एशिया में संवाद और कूटनीति के माध्यम से दीर्घकालिक शांति की जरूरत दोहराई है। भारत ने भी लगातार यही रुख अपनाया है कि युद्ध किसी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकता और बातचीत तथा कूटनीति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इस दृष्टिकोण से भारत एक ऐसे देश के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है जो अलग-अलग पक्षों के बीच संवाद का रास्ता खुला रखने में विश्वास करता है। ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की द्विपक्षीय मुलाकात भी विशेष चर्चा में रही। दोनों नेताओं ने भारत-चीन संबंधों को आगे बढ़ाने और मतभेदों को विवाद में नहीं बदलने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट कहा कि दोनों देशों के संबंधों के निरंतर विकास के लिए सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता आवश्यक है। उन्होंने आपसी सम्मान, आपसी संवेदनशीलता और आपसी हित के सिद्धांतों का पालन करने की जरूरत भी बताई। चीन के राष्ट्रपति ने दोनों देशों के एक-दूसरे की ताकत से सीखने और साझा विकास की दिशा में आगे बढ़ने की बात कही। इस बातचीत से यह संकेत जरूर मिला कि दोनों देश तनाव कम करने और संबंधों में व्यावहारिक सुधार की संभावनाएं तलाश रहे हैं, हालांकि सीमा विवाद जैसे जटिल मुद्दों का समाधान समय और निरंतर संवाद से ही संभव होगा।

भारत-चीन संबंधों में सामान्य स्थिति की ओर बढ़ने का एक संकेत दोनों देशों के बीच हवाई संपर्क की बहाली भी है। चीन की विमानन कंपनी द्वारा 21 सितंबर से ग्वांगझू और नई दिल्ली के बीच नियमित उड़ान सेवा फिर शुरू करने की घोषणा दोनों देशों के लोगों और व्यापारिक संबंधों के लिए सकारात्मक कदम है। कोविड महामारी के बाद निलंबित हुई उड़ान सेवाओं और सीमा तनाव के कारण दोनों देशों के बीच संपर्क प्रभावित हुआ था। हवाई संपर्क की बहाली से व्यापार, पर्यटन और लोगों के बीच संबंधों को गति मिलने की उम्मीद की जा सकती है।

इस पूरे घटनाक्रम के बीच भारत की आर्थिक स्थिति से जुड़ी एक और सकारात्मक खबर सामने आई है। चार सितंबर को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 44.9 अरब डॉलर बढ़कर 785.7 अरब डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। इस वृद्धि के साथ भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में रूस को पीछे छोड़कर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा भंडार रखने वाला देश बन गया है। भारत से आगे चीन, जापान और स्विट्जरलैंड हैं। विदेशी मुद्रा भंडार में इतनी बड़ी वृद्धि ऐसे समय हुई है जब वैश्विक अर्थव्यवस्था कई तरह की अनिश्चितताओं से गुजर रही है। मजबूत विदेशी मुद्रा भंडार भारत को वैश्विक आर्थिक उतार-चढ़ाव के दौरान अपनी मुद्रा और अर्थव्यवस्था को अधिक मजबूती से संभालने की क्षमता देता है।

ब्रिक्स सम्मेलन की तस्वीर को यदि व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत के सामने केवल एक शिखर सम्मेलन की सफलता नहीं बल्कि वैश्विक नेतृत्व की नई संभावना दिखाई देती है। आतंकवाद के खिलाफ साझा सहमति, पहलगाम हमले की निंदा, सुरक्षा परिषद में भारत की बड़ी भूमिका का समर्थन, वैश्विक दक्षिण को निर्णय प्रक्रिया में अधिक अधिकार देने की आवाज, आर्थिक व्यवस्था में सुधार की मांग, पश्चिम एशिया में संवाद और शांति का आग्रह तथा चीन के साथ संबंधों में तनाव कम करने की कोशिश, इन सभी घटनाओं को एक साथ रखकर देखा जाए तो भारत की कूटनीति का व्यापक स्वरूप सामने आता है। भारत की ताकत केवल आर्थिक विकास या सैन्य क्षमता में नहीं बल्कि अलग-अलग विचारधारा और हित रखने वाले देशों को संवाद की मेज पर लाकर सहमति बनाने की क्षमता में भी दिखाई दे रही है। दिल्ली घोषणापत्र इसी क्षमता का प्रमाण है। आने वाले समय में ब्रिक्स कितना प्रभावी वैश्विक मंच बनता है, यह उसके सदस्य देशों की घोषणाओं को वास्तविक नीतियों में बदलने की क्षमता पर निर्भर करेगा। लेकिन इतना स्पष्ट है कि नई दिल्ली में हुए सम्मेलन ने भारत को केवल मेजबान देश के रूप में नहीं बल्कि बदलती विश्व व्यवस्था में एक सक्रिय, संतुलित और निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित किया है। यही इस सम्मेलन की सबसे बड़ी उपलब्धि है।

भारतीय दार्शनिक सम्प्रदाय

3-यज्ञ-प्रक्रिया के क्षेत्र में दर्शन शास्त्र का विकास

गतांक से आगे...

वेद के पूर्व-भाग अथवा कर्मकाण्ड सम्बन्धी भाग से सम्बद्ध शास्त्र का नाम पूर्वमीमांसा और वेद के उत्तर भाग या ज्ञान काण्ड से सम्बद्ध शास्त्र का नाम उत्तर मीमांसा है, इस प्रकार वेदों के अथवा यह कहना अधिक उचित होगा कि ब्राह्मणों के, पहले और पिछले भागों से सम्बन्ध रखने के कारण ये दोनों शास्त्र पूर्व और उत्तर मीमांसा कहलाते हैं, मानों वे दोनों एक ही शास्त्र के पहले और पिछले दो भाग हों, परन्तु यह स्पष्ट है कि इन दोनों शास्त्रों के दार्शनिक सिद्धान्तों में परस्पर कोई समता या सङ्गति नहीं है, जैसा कि आगे स्पष्ट किया जाएगा।

जहां तक मीमांसा शास्त्र का सम्बन्ध है, उसमें केवल ब्राह्मण-ग्रन्थों के कर्म काण्ड का निरूपण है। साथ ही ब्राह्मण-ग्रन्थों के वाक्यों का समन्वय और सङ्गति करने के लिये, वाक्य के तात्पर्य का विवेचन करने वाले एक नये विज्ञान की, जिसे हम वाक्य विज्ञान कह सकते हैं, स्थापना की गयी है, मीमांसा में जो कुछ दार्शनिक तत्त्व हैं, वह पिछले युग के मीमांसा शास्त्र के आचार्य कुमारिल और प्रभाकर की देन है, जिनका जन्म सम्भवत: 8 वीं शताब्दी में हुआ। वैदिक दर्शनों में वेदान्त तो साक्षाद्रूपेण उपनिपदों के सिद्धान्त से सम्बन्ध रखने वाला दर्शन है ही, और सांख्य तथा योग भी उपनिषदों पर ही आश्रित दर्शन हैं।

मीमांसा-दर्शन ब्राह्मणों के यज्ञ-सम्बन्धी कर्मकाण्ड से सम्बन्ध रखता ही है। शेष दो वैदिक दर्शन न्याय और वैशेषिक रह जाते हैं। उनका सम्बन्ध न तो उपनिषदों से ही है और न किसी प्रकार ब्राह्मणों के कर्म-काण्ड से ही प्रतीत होता है। यह स्पष्ट है कि उपनिषदों का सिद्धान्त कि जगत् ब्रह्म की अभिव्यक्ति है और ब्रह्म को छोड़कर उसकी कोई यथार्थता नहीं, यज्ञ-सम्बन्धी कर्मकाण्ड का विरोधी है।

क्रमशः ...

श्री हरि ने किया असुर पुत्रों का उद्धार

आशुतोष गर्ग

जब भगवान विष्णु और देवताओं के अंश पृथ्वी पर अवतरित होने लगे, तब देवर्षि नारद कंस को उसके निकट आते विनाश की सूचना देने मथुरा पहुंचे। उन्होंने कंस से कहा, 'तुम्हारी छोटी बहन देवकी का आठवां गर्भ तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। वह गर्भ देवताओं का सर्वस्व और स्वर्गलोक का आश्रय होगा।' यह सुनते ही कंस भयभीत हो उठा। उसने अपनी रक्षा के उपायों पर मंत्रियों के साथ विचार करना शुरू किया।

श्रीहरि ने यह सब जानकर सोचा कि कंस देवकी के सात गर्भों को नष्ट कर देगा। इसलिए, अपनी अवतार-योजना को पूरा करने के लिए पहले से ही आवश्यक व्यवस्था करनी होगी। उसी समय भगवान का ध्यान पाताल लोक में रहने वाले छह दैत्यों की ओर गया। ये छहों हिरण्यकशिपु के वंशज और कालनेमि के पुत्र थे। कालनेमि ने इन छहों को मिलाकर 'षड्गर्भ' नाम दिया था। वे अपने पितामह हिरण्यकशिपु को छोड़कर ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए और बोले, 'दानवकुल के वीरो! मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। तुम जो वर चाहते हो, मांग लो।' षड्गर्भ ने एक ही स्वर में वर मांगा, 'भगवन! हमारा वध देवताओं, नागों, यक्षों, गंधर्वों, सिद्धों, चारणों और मनुष्यों से न हो। महर्षियों के शाप से भी हमारा अहित न हो।' ब्रह्मा जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्हें अभय का वर प्रदान करके ब्रह्मलोक चले गए।

जब हिरण्यकशिपु को पता चला कि उसके पौत्रों ने ब्रह्मा जी की आराधना की है, तो वह अत्यंत क्रोधित हुआ। उसने कहा, 'तुमने मुझे छोड़कर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया है, इसलिए अब तुम मेरे प्रिय नहीं रहे। तुमने अपने ही कुल और मेरे स्नेह का अपमान किया है।' क्रोध में उसने उन्हें शाप दे दिया, 'तुम छहों अगले जन्म में गर्भ में रहोगे और तुम्हारा वध होगा। तुम देवकी के गर्भ में जन्म लोगे और कंस तुम्हें एक-एक करके मार डालेगा।' समय आने पर भगवान विष्णु ने अपनी योजना के अनुसार पाताल लोक का स्मरण किया। वहां षड्गर्भ नामक वे छहों दैत्य जल के भीतर एक गर्भगृह में योगनिद्रा में सो रहे थे। भगवान उनके पास पहुंचे और अपनी शक्ति से उनके जीवों को निद्रा की अधिष्ठात्री देवी के संरक्षण में सौंप दिया। फिर उन्होंने निद्रा देवी से कहा, 'मेरी प्रेरणा से इन छहों जीवों को पृथ्वी पर ले जाओ और क्रमश: देवकी के गर्भ में स्थापित करो। कंस इन्हें जन्म लेते ही मार डालेगा। इस प्रकार इनके पूर्वजन्म का शाप भी पूरा होगा और मेरी आगे की योजना का मार्ग भी प्रशस्त होगा।' भगवान ने आगे कहा, 'देवकी का सातवां गर्भ मेरा सौम्य अंश होगा। वह मेरा बड़ा भाई बनेगा। जब गर्भ सात महीने का हो जाए, तब तुम उसे देवकी के गर्भ से निकालकर रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर देना। गर्भ के इस प्रकार खींचे जाने के कारण वह 'संकर्षण' नाम से प्रसिद्ध होगा। लोग उसे बलराम के नाम से जानेंगे।' फिर, भगवान ने कहा, 'जब मैं आठवें गर्भ के रूप में देवकी के यहां जन्म लूंगा, तब कंस मुझे मारने का प्रयास करेगा। इस प्रकार श्रीहरि की योजनानुसार घटनाएं घटित हुईं। षड्गर्भों का पूर्वजन्म का शाप पूरा हुआ।

आतंकी मसूद पर पाकिस्तान की नई नौटंकी

सुरेश हिंदुस्तानी

आतंकवाद के प्रश्न पर पाकिस्तान की भूमिका लंबे समय से विश्व समुदाय के लिए चिंता का विषय रही है। आतंकवाद के विरुद्ध कठोर कार्रवाई का दिखावा और आतंकी संगठनों के प्रति नरम रवैया, पाकिस्तान की विदेश एवं सुरक्षा नीति के इस विरोधाभासी चरित्र ने उसकी विश्वसनीयता को लगातार कठघरे में खड़ा किया है। आतंकी सरगना मसूद अजहर को लेकर पाकिस्तान की हालिया कार्रवाई भी इसी विरोधाभास की एक नई कड़ी के रूप में देखी जा रही है। उसे भगोड़ा घोषित करना और उसकी गिरफ्तारी पर इनाम की घोषणा करना पहली दृष्टि में कठोर कार्रवाई का संकेत देता है, लेकिन पाकिस्तान के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए इसके पीछे की वास्तविक मंशा पर प्रश्न उठना स्वाभाविक है।

मसूद अजहर कोई सामान्य अपराधी नहीं है। वह भारत में हुए अनेक आतंकी हमलों से जुड़े उन कुख्यात चेहरों में रहा है, जिनकी गतिविधियों ने न केवल भारत की सुरक्षा को चुनौती दी, बल्कि दक्षिण एशिया में आतंकवाद के नेटवर्क की भयावहता को भी उजागर किया। वर्ष 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान के अपहरण के बाद यात्रियों की रिहाई के बदले भारत को जिन आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा, उनमें मसूद अजहर भी शामिल था। इसके बाद उसने आतंकवादी गतिविधियों के जिस नेटवर्क को आगे बढ़ाया, उसने भारत की सुरक्षा व्यवस्था के सामने गंभीर चुनौतियां खड़ी कीं।

विडंबना यह है कि जिस व्यक्ति को भारत लंबे समय से आतंकवाद का प्रमुख चेहरा मानता रहा है, उसी मसूद अजहर को लेकर पाकिस्तान अब यह दावा कर रहा है कि वह उसकी पकड़ से बाहर है और संभवत: अफगानिस्तान में छिपा हुआ है। यदि यह दावा सही है तो सवाल यह उठता है कि पाकिस्तान की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां इतने कुख्यात आतंकी के संबंध में इतनी अनभिज्ञ कैसे हो सकती हैं? और यदि वह पाकिस्तान से बाहर है तो उसके संगठनात्मक नेटवर्क, आर्थिक संसाधनों और संपर्कों पर कार्रवाई क्यों दिखाई नहीं देती? यहीं से पाकिस्तान की कार्रवाई पर संदेह की परतें गहरी होने लगती हैं।

पाकिस्तान की जांच एजेंसी एफआईए द्वारा मसूद अजहर को अपने अत्यंत खतरनाक आतंकवादियों की सूची में शामिल किया जाना अपने आप में महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। लेकिन केवल किसी आतंकी को सूचीबद्ध कर देना आतंकवाद के विरुद्ध निर्णायक कार्रवाई नहीं माना जा सकता। असली कसौटी गिरफ्तारी, न्यायिक प्रक्रिया, आतंकी नेटवर्क का विघटन और उसके वित्तीय स्रोतों पर प्रभावी प्रहार है। यदि कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित रह जाए, तो वह आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय दबाव को टालने की प्रशासनिक कवायद बनकर रह जाती है।

भारत के सुरक्षा तंत्र से जुड़े इनपुट यदि यह संकेत देते हैं कि मसूद अजहर पाकिस्तान में ही छिपा हुआ है, तो पाकिस्तान के दावे की विश्वसनीयता और भी संदिग्ध हो जाती है। हालांकि ऐसे खुफिया दावों की स्वतंत्र पुष्टि आवश्यक होती है, लेकिन पाकिस्तान का अतीत उसके वर्तमान दावों पर सहज विश्वास करने की अनुमति नहीं देता।

पाकिस्तान का यह दोहरा चरित्र नया नहीं है। दुनिया पहले भी देख चुकी है कि आतंकवाद के विरुद्ध कार्रवाई का दावा करने वाला पाकिस्तान अपनी ही धरती पर छिपे कुख्यात आतंकवादियों की मौजूदगी से लंबे समय तक इनकार करता रहा। ओसामा बिन लादेन का पाकिस्तान में पाया जाना इस संदर्भ में सबसे चर्चित उदाहरण है। अमेरिकी कार्रवाई में एबटाबाद में लादेन के मारे जाने के बाद पाकिस्तान के उन दावों की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्न उठे थे, जिनमें वह अपनी धरती पर आतंकवादी सरगनाओं की मौजूदगी से अनभिज्ञता जताता रहा था।

आतंकी मसूद अजहर पर पाकिस्तान सरकार की कार्यवाही को इसलिए भी संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में आतंकी सरगनाओं पर न तो सरकार का नियंत्रण है और न ही सेना की ही चलती है। आतंकियों का अपना एक तंत्र है। जिनमें कोई भी दखल नहीं दे सकता। पाकिस्तान में तीन शक्ति केंद्र माने जाते हैं, जिनमें सरकार, सेना और आतंकवादी हैं। कई बार यह भी देखने में आता है कि वहां की सरकार किसकी होगी, यह आतंकी और सेना तय करती है। इसलिए सरकार, आतंकियों पर कठोर कार्यवाही करने का सामर्थ्य नहीं जुटा पाती। और आतंकी फलीभूत होते रहते हैं।

इस पृष्ठभूमि में मसूद अजहर पर घोषित इनाम को केवल कानून-व्यवस्था की कार्रवाई के रूप में देखना कठिन है। इसके पीछे पाकिस्तान की अंतरराष्ट्रीय छवि सुधारने की मंशा भी दिखाई देती है। विशेषकर आतंकवाद के वित्तपोषण और धनशोधन से जुड़े अंतरराष्ट्रीय मानकों के संदर्भ में पाकिस्तान पर लगातार दबाव रहा है। ऐसे समय में किसी कुख्यात आतंकी के विरुद्ध सार्वजनिक कार्रवाई का प्रदर्शन अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को यह संदेश देने का प्रयास हो सकता है कि पाकिस्तान आतंकवाद के विरुद्ध सक्रिय है।

लेकिन आज विश्व पहले की तुलना में कहीं अधिक सतर्क है। आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में अब केवल घोषणाएं पर्याप्त नहीं हैं। अंतरराष्ट्रीय समुदाय यह देखता है कि आतंकवादी संगठनों की वित्तीय धमनियां कितनी प्रभावी ढंग से रोकी गईं, उनके प्रशिक्षण शिविरों और नेटवर्क पर क्या कार्रवाई हुई, आतंकी सरगनाओं को न्याय के कठघरे में कब लाया गया और आतंकवाद को संरक्षण देने वाली संरचनाओं को कितना ध्वस्त किया गया।

पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति भी उसके लिए एक बड़ी चुनौती है। विदेशी सहायता, ऋण और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से मिलने वाली आर्थिक सहायता उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे में आतंकवाद के वित्तपोषण को लेकर अंतरराष्ट्रीय दबाव उसके आर्थिक हितों से सीधे जुड़ जाता है। यदि पाकिस्तान आतंकवाद पर प्रभावी कार्रवाई करने में विफल रहता है तो उस पर आर्थिक एवं वित्तीय प्रतिबंधों का दबाव बढ़ सकता है। इसलिए उसके द्वारा की जाने वाली प्रत्येक कार्रवाई को उसके आर्थिक और कूटनीतिक संदर्भ में भी परखना आवश्यक है।

भारत के लिए यह समय पाकिस्तान के किसी भी दावे से प्रभावित होने के बजाय तथ्यों, प्रमाणों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के आधार पर अपनी आतंकवाद विरोधी नीति को और सुदृढ़ करने का है। आतंकवाद किसी एक देश की समस्या नहीं है। यह वैश्विक शांति, लोकतांत्रिक संस्थाओं और मानव सभ्यता के लिए चुनौती है। इसलिए आतंकवाद को संरक्षण देने वाली किसी भी व्यवस्था के प्रति अंतरराष्ट्रीय समुदाय को शून्य-सहनशीलता की नीति अपनानी होगी।

मसूद अजहर पर इनाम की घोषणा यदि वास्तविक कार्रवाई की दिशा में पहला कदम है तो पाकिस्तान को उसे प्रमाणित करने में देर नहीं करनी चाहिए। उसे चाहिए कि वह मसूद अजहर की वास्तविक स्थिति स्पष्ट करे, यदि वह पाकिस्तान में है तो उसे गिरफ्तार करे, उसके नेटवर्क को ध्वस्त करे और उसके विरुद्ध पारदर्शी न्यायिक कार्रवाई सुनिश्चित करे। अन्यथा यह कार्रवाई भी पाकिस्तान की उन अनेक घोषणाओं की सूची में जुड़ जाएगी, जिनमें शब्द बहुत थे, लेकिन परिणाम नगण्य। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में अब दुनिया को दावों की नहीं, कार्रवाई की भाषा चाहिए।

आज का इतिहास

1795 ब्रिटेन ने दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन पर कब्जा किया।
1810 निगवेल हिदाल्गो ने स्पेन से मैक्सिको की आज़ादी के लिए संघर्ष शुरु किया।
1821 मैक्सिको की स्वतंत्रता को मान्यता मिली।
1848 फ्रांसीसी उपनिवेश से दास प्रथा खत्म की गई।
1908 जनरल मोटर्स निगम की स्थापना की गई।
1943 सोवियत संघ की सेना के जनरल वातुतिन ने दोबारा रोमनी पर कब्जा किया।
1947 टोक्यो के सईतामा में चक्रवाती तूफान कैथलीन से 1,930 लोगों की मौत हो गई।
1963 मलया सिंगापुर ब्रिटिश नार्दन वौनियो से मलेशिया का गठन हुआ।
1975 केप वर्डे, मोजाम्बिक, साओ टोमे और प्रिंसिप संयुक्त राष्ट्र में शामिल हुए।
1975 पापुआ न्यू गिनी ने आस्ट्रेलिया से स्वतंत्रता हासिल की।
1978 जनरल जिया उल हक़ पाकिस्तान के राष्ट्रपति निर्वाचित।
1978 ईरान में आए भूकंप में 20 हजार से भी ज्यादा लोग मारे गए।
1986 दक्षिण अफ्रीका की एक सोने की खदान में फंस जाने से 177 लोग मारे गए।
2003 भूटान ने भारतीय हितों के खिलाफ़ अपनी ज़मीन के इस्तेमाल नहीं होने देने का आश्वासन दिया।
2007 पाकिस्तान के मुख्य चुनाव आयुक्त ने परवेज मुशर्रफ़ के राष्ट्रपति पद पर दुबारा चुनाव लड़ने के लिए चुनाव से जुड़े क़ानूनों में संशोधन किया।
2007 वन टू गो एयरलांइस का विमान थाईलैंड में दुर्घटनाग्रस्त होने से 89 लोगों की मौत।
2008 भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) के कर्मचारियों को विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किया गया।
2009 दुनिया भर के समक्ष भारत के एक उत्कृष्ट पर्यटन स्थल के रूप में पेश करने वाले अतुल्य भारत विज्ञान अभियान को ब्रिटिश पुरस्कार मिला।
2013 वाशिंगटन में एक बंदूकधारी ने नौसेना के एक शिविर में 12 लोगों की गोली मारकर हत्या की।
2014 इस्लामिक स्टेट ने सीरियाई कुर्दिश लड़ाकों के खिलाफ युद्ध छेड़ा।
2017 भारतीय वायुसेना के सबसे वरिष्ठ एवं पांच सितारा रैंक पर पहुंचने वाले एकमात्र मार्शल अर्जन सिंह का निधन हुआ था।
2020 विदुषी, लेखिका और कलाविद डॉ. कपिला वात्स्यायन का निधन हुआ।

दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी-जिनपिंग की मुलाकात से उम्मीदें

सुबीर भौमिक

ऐसे वक्त में, जब अमेरिका दुनिया को पश्चिम एशिया और यूक्रेन में चल रहे युद्धों की ओर धकेल रहा है, एशिया के दो बड़े देश-भारत और चीन-अपने संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली में हाल ही में हुए 18वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात ने दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव को कम करने की नई उम्मीद जगाई है। यदि दोनों देश अपने विवादों को बातचीत और समझ के जरिये सुलझाने में सफल होते हैं, तो यह दुनिया के सामने शांतिपूर्ण तरीके से विवाद सुलझाने का एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है। चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के लिए भारत की दावेदारी का समर्थन करने में अन्य ब्रिक्स देशों का साथ दिया है। यह दिल्ली के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।

इस विवाद को सुलझाने के मूल में एक सभ्यतागत गुण है और वह है पूरी तरह से अलग व्यवस्था या संस्कृति के प्रति सहनशीलता। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान चीन की ओर से जारी एक वीडियो में इसका जिक्र किया। शी जिनपिंग ने कहा, 'हालांकि हमारे देश कई मामलों में बिल्कुल अलग हैं, फिर भी हम एक-दूसरे की खूबियों को पूरा करने, एक-दूसरे का समर्थन करने, आपसी सफलता हासिल करने और साथ मिलकर आगे बढ़ने में पूरी तरह सक्षम हैं।' प्रधानमंत्री मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात के बारे में भारत के विदेश मंत्रालय के एक बयान में कहा गया- 'दोनों नेताओं ने सीमा विवाद के निष्पक्ष, उचित और आपसी सहमति वाले समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई।'

हिमालय की लंबी और सुनसान सीमा पर लंबे समय से चले आ रहे विवाद के कारण 1962 में भारत और चीन के बीच एक छोटा-सा युद्ध हुआ था और अक्सर सीमा पर स्थित दोनों देशों की सेनाओं के बीच झड़पें व टकराव होते रहे हैं। इनमें सबसे हालिया घटना 2020 में लद्दाख की गलवां घाटी में हुई झड़प है। भारतीय विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है, 'प्रधानमंत्री मोदी ने सीमा से जुड़े मुद्दों पर मौजूदा समझौतों और आपसी समझ का दोनों पक्षों द्वारा पालन किए जाने की जरूरत पर जोर दिया।'

दोनों नेताओं की बातचीत केवल सीमा विवाद तक सीमित नहीं रही। इस द्विपक्षीय वार्ता में जोर देकर दोनों नेताओं ने भारत व चीन के बीच सांस्कृतिक, व्यापारिक और परिवहन संबंधों को बढ़ाने का वादा किया। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया, 'आर्थिक और व्यापारिक संबंधों पर, उन्होंने (मोदी और शी जिनपिंग) एक-दूसरे की चिंताओं को दूर करने की जरूरत पर बल दिया, जिसमें व्यापार में संरचनात्मक असंतुलन और आपूर्ति शृंखला से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। साथ ही, सार्थक और

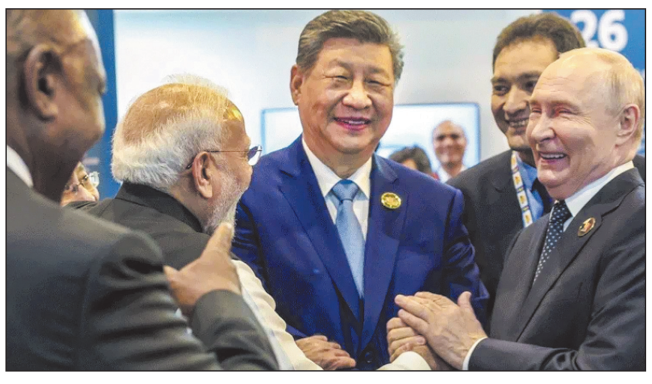

अनुमान लगाने योग्य बाजार पहुंच की सुविधा भी शामिल है।' भारत लंबे समय से चीन के साथ व्यापार घाटे को कम करने और भारतीय उत्पादों के लिए बेहतर बाजार पहुंच की मांग करता रहा है। ऐसे में दोनों देशों के बीच व्यापार को अधिक संतुलित और पूर्वानुमान योग्य बनाना महत्वपूर्ण होगा।

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान शी जिनपिंग और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई द्विपक्षीय बातचीत से यह बिल्कुल साफ हो गया है कि भारत और चीन, दोनों ही सीमा विवाद को सुलझाने की दिशा में मिलकर काम करने पर सहमत हो गए हैं। यह उस पुरानी नीति से एक बड़ा बदलाव है, जिसमें सीमा विवाद को सुलझाने की बातचीत धीमी गति से चलने के बावजूद व्यापार और दूसरे संबंध बढ़ाकर सीमा विवाद से अलग हटकर काम किया जाता था। यह सोच 1980 के दशक में देंग शियाओपिंग और राजीव गांधी के बीच हुई बातचीत से सामने आई थी और इसके बाद 1993 में शांति और अमन-चैन की संधि हुई थी।

इस नीति का अच्छा नतीजा निकला कि सीमा विवाद सुलझे बिना भी शांतिपूर्ण माहौल में व्यापार जारी रह सकता है, क्योंकि चीन अब भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। लेकिन दोकलाम (2017) और गलवां (2020) में हुई झड़पों ने सीमा विवाद के अहम मुद्दे और रिश्तों को सामान्य बनाने की प्रक्रिया को पटरी से उतारने की इसकी क्षमता को फिर से उजागर कर दिया। भारत के लिए, सीमा विवाद का स्थायी समाधान सैन्य तैनाती पर होने वाले खर्च को कम करने के लिहाज से एक वरदान साबित होगा, जिससे सेना के आधुनिकीकरण के लिए ज्यादा धन उपलब्ध हो सकेगा। इससे आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान और बांग्लादेश में तेजी से बढ़ते इस्लामी शासन के साथ 'हाइब्रिड संघर्ष' से निपटने पर भारतीय सेना का पूरा ध्यान केंद्रित करना आसान हो जाएगा। चीन का निवेश न केवल 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा देगा, बल्कि चीन के साथ व्यापार असंतुलन को कम करने में भी मदद करेगा।

बीजिंग के लिए, सीमा विवाद सुलझने के बाद एक दोस्ताना भारत के पास सैन्य या किसी और तरह से अमेरिका की ओर झुकने की बहुत कम वजह होगी। खासकर, ताइवान को लेकर पश्चिम के साथ संभावित टकराव को देखते हुए शी जिनपिंग के पास भारत से रिश्ते सुधारने का यह एक बड़ा कारण है। इसलिए, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत के बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दिल्ली में कहा कि बीजिंग ने हमेशा चीन-भारत रिश्तों को रणनीतिक और लंबे समय के नजरिये से देखा और विकसित किया है। चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ ने इस बात को प्रमुखता से प्रकाशित भी किया है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान हुई यह द्विपक्षीय बातचीत हाल ही में बीजिंग में हुई सीमा विवाद सुलझाने की बातचीत के 25वें दौर के बाद हुई, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल ने सीमा विवाद को जल्द सुलझाने पर जोर दिया था। इससे पूर्व, चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने एक महीने पहले दिल्ली का दौरा किया था।

अगर अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के पहले दशक की सबसे अहम घटना थी, तो चीन के साथ सीमा विवाद सुलझाना और उससे दोस्ती करना उनके मौजूदा कार्यकाल की मुख्य विदेश नीति साबित हो सकती है।

दुनिया को नए नक्शे की जरूरत क्यों है?

विकास मिश्रा

विश्व के मानचित्र पर भारत के आकार पर क्या आपने कभी ध्यान दिया है? क्या वास्तव में भारत का आकार उतना ही है जितना विश्व मानचित्र पर दिखता है? जी नहीं! हकीकत यह है कि नक्शे में भारत का आकार उसकी वास्तविक जमीन से काफी छोटा दिखाई देता है। ऐसा और भी देशों के साथ है। इसका मुख्य कारण यह है कि धरती गोल है और नक्शा सपाट कागज पर होता है। तो इसका हल क्या है? इसका हल है वास्तविकता के आधार पर इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसी महीने यानी चार सितंबर को नया नक्शा पास तैयार करने का प्रस्ताव पास किया है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं भारत की। भारत का क्षेत्रफल लगभग 32 लाख 87 हजार 263 वर्ग किलोमीटर है, जो दुनिया के कुल भूभाग का लगभग 2 ।4त्न है। यानी क्षेत्रफल के मामले में भारत दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है। तो नक्शे पर उसे उतना बड़ा दिखना चाहिए, मगर दिखता नहीं है। इसी तरह विश्व के मानचित्र पर ग्रीनलैंड, उत्तरी अमेरिका, कनाडा और रूस जैसे देश अपने वास्तविक आकार से काफी बड़े दिखाई देते हैं। जो देश भूमध्य रेखा के पास स्थित हैं वे काफी हद तक नक्शे पर सही आकार में दिखते हैं मगर जैसे-जैसे हम भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण ध्रुव की ओर बढ़ते हैं, नक्शे पर जमीन का आकार ज्यादा खिंचा हुआ यानी बड़ा दिखाई देने लगता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्रीनलैंड, अफ्रीका महाद्वीप के करीब-करीब बराबर दिखाई देता है जबकि वास्तविकता यह है कि अफ्रीका महाद्वीप, ग्रीनलैंड से 14 गुना बड़ा है। वास्तव में ग्रीनलैंड तो आकार में भारत से भी छोटा है। नक्शे में रूस और कनाडा अफ्रीका महाद्वीप को घेरते हुए बहुत विशाल दिखाई देते हैं जबकि हकीकत यह है कि अफ्रीका का क्षेत्रफल कनाडा और रूस के कुल क्षेत्रफल से भी बड़ा है। तो सवाल है कि इस तरह का नक्शा तैयार ही क्यों किया गया? यह नक्शा फ्लेमिश भूगोलवेत्ता और मानचित्रकार गेरार्डस मर्केटर ने 1569 में तैयार किया था और इसका उद्देश्य नाविकों को दिशा देना था। इस लिहाज से मर्केटर मैप उपयोगी साबित हुआ क्योंकि इसमें दिशा और कोण एकदम सही और सीधी रेखाओं में दिखाई देते हैं। यही कारण है कि दुनियाभर ने इस नक्शे को अपनाया और दिशा और कोण सटीकता के कारण पिछले साढ़े चार सौ साल से भी ज्यादा समय से यह उपयोग में है। अब तकनीक बदली है और इस बीच विभिन्न देशों से ये सुझाव भी आते रहे कि नई तकनीक पर आधारित एक ऐसा नक्शा बनाया जाए जो देशों के आकार को सटीक यानी वास्तविकता के करीब दर्शा सके। 2018 में अमेरिका में कार्यरत और मूल रूप से स्लोवेनिया के रहने वाले मानचित्रकार बोजन शाव्रिक, अमेरिकी मानचित्रकार टॉम पैटरसन और मूल रूप से स्विट्जरलैंड के रहने वाले बर्नहार्ड जेनी ने इक्वल अर्थ प्रोजेक्शन मैप विकसित किया। इस साल संयुक्त राष्ट्र ने नक्शे का प्रारूप प्रकाशित किया। भारत ने इक्वल अर्थ नक्शे का प्रारंभ से ही समर्थन किया है लेकिन जब प्रारूप सामने आया तो भारत ने इस पर गंभीर आपत्ति जताई क्योंकि भारत के कुछ हिस्से को इसमें गलत तरीके से दर्शाया गया है। संयुक्त राष्ट्र के नए नक्शे में जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चिन को विवादित क्षेत्र के रूप में दिखाया गया है। भारत ने स्पष्ट तौर पर कहा कि संयुक्त राष्ट्र का ये नया नक्शा भारत की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ है और इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर राज्यों की सीमाएं भारत के आधिकारिक नक्शे के अनुसार ही दर्शाई जानी चाहिए। मानचित्र में कोई भी छेड़छाड़ अस्वीकार्य है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में नक्शे का समर्थन पुरानी भौगोलिक विकृतियों को दूर करने और महाद्वीपों के वास्तविक आकार को दिखाने के लिए किया था, न कि इसलिए कि कोई हमारी भौगोलिक संप्रभुता के साथ छेड़छाड़ करे! हालांकि अभी यह पता नहीं है कि यह छेड़छाड़ किसने की है मगर एक बात तो साफ समझ में आती है कि यह किसी षड्यंत्र का हिस्सा हो सकता है।

जर्मनी में कट्टर दक्षिणपंथी राजनीति का पुनरुत्थान

बिलाल भट्ट

इतिहासकार एरिक हॉब्सबॉम ने अपनी किताब द एज ऑफ एक्सट्रीम्स में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण का वर्णन सिर्फ दो शब्दों में किया था: एडॉल्फ हिटलर। यह वह समय था जब पूरी दुनिया में यहूदियों के प्रति नफरत चुपचाप, लेकिन जंगल की आग की तरह फैल गई थी। यहूदी-विरोधी यह भ्रामक धारणा कि यहूदी ईसाई बच्चों की बलि देते थे, दुनिया के कुछ हिस्सों में अब भी मानी जा सकती है।

जब हम इसकी नाज़ी जर्मनी, फासीवाद, राजनीतिक हत्याओं और हमारे आस-पास की समकालीन दुनिया के संघर्षों के दौर से तुलना करते हैं, तो ऐसा लगता है कि इतिहास और भी अधिक कपटी किरदारों के साथ वापस लौट रहा है। चरमपंथ की मशाल फिर से जल उठी है, चरमपंथ का धुआं फिर से उठ रहा है, और कट्टर दक्षिणपंथ की वापसी हो रही है।

दिखावटी सुधार या राजनीतिक बहकावे को छोड़ दिया जाए, तो मूल बातें जस की तस हैं। जो पार्टियां खुद को फासीवाद या नाज़ीवाद से नहीं जोड़ना चाहतीं, वे सुविधाजनक रूप से खुद को सिर्फ दक्षिणपंथी के रूप में ब्रांड करती हैं; उदाहरण के लिए, स्पेन की राजनीतिक पार्टी Vox खुद को फासीवाद-विरोधी, नाज़ीवाद-विरोधी और दक्षिणपंथी बताती है।

यह विरोधाभास हर जगह फैला हुआ है, और उनका यह दोहरापन उनके काम आ रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका का यह दावा कि वह शांति बहाल करने के लिए युद्ध लड़ रहा है, उतना ही खोखला है जितना कि अफगानिस्तान में शांति बहाल करने का उनका दावा, जिसके बाद वे वहां एक अधिक मजबूत तालिबान छोड़ गए, या फिर

गाजा के पुनर्निर्माण के दावे, जहां बच्चे और महिलाओं सहित आम नागरिक आज भी बंदूकों और बमों के साये में जी रहे हैं।

सद्दाम हुसैन की हत्या ने ईरान को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत बना दिया, जिससे पूरा क्षेत्र आईएसआईएस जैसे समूहों के पनपने का ठिकाना बन गया।

20वीं सदी के विश्व युद्धों के दौरान लोगों के पास जो तर्क थे और जो तर्क लोग अब पेश करते हैं, वे वास्तव में न्यायसंगत हैं या नहीं, यह बहस का विषय है, लेकिन एकमात्र अंतर जो कोई देख सकता है वह यह है कि कुछ व्यवहारों को इस हद तक सामान्य मान लिया गया है कि अब असामान्य व्यवहार को असामान्य नहीं देखा जाता।

यूक्रेन को सैन्य मदद देने का विरोध करने वालों का मानना है कि वे उन लोगों के मुकाबले इतिहास के सही रास्ते पर हैं जो बिना सोचे-समझे यूक्रेन को सैन्य सहायता का समर्थन करते हैं।

युद्ध में उलझे देशों को लेकर लोगों की राय बंटी हुई है, चाहे वह यूक्रेन-रूस युद्ध हो या पश्चिम एशिया का युद्ध; कुछ लोगों का मानना है कि तटस्थ रहना ठीक है, कुछ का कहना है कि चुप रहना भी अपराध में शामिल होने जैसा है, और कुछ लोग किसी एक का पक्ष लेते हैं, और इनमें से हर किसी के पास खुद को सही साबित करने के लिए अपनी एक कहानी है।

इन बातों को उस दौर से जोड़कर देखें जब हिटलर को उसके कृत्यों के लिए तिरस्कार की भावना से देखा जाता था, तब कम से कम एक आम सहमति थी। अब वे विभाजन रेखाएं धुंधली पड़ गई हैं, बल्कि कहें तो कमजोर हो गई हैं, और पूर्वी जर्मनी का चुनाव परिणाम इसका एक सटीक उदाहरण है।

दक्षिणपंथी पार्टी ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी, अब सैक्सनी-एनहाल्ट में अपनी पहली जीत के बाद सत्ता में आने का लक्ष्य बना रही है, जहां उसने 2002 से राज्य पर शासन करने वाली मध्य-दक्षिणपंथी पार्टी को हरा दिया।

ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी एक ऐसी पार्टी है जिसे सरकारी खुफिया एजेंसी ने एक चरमपंथी गुट के रूप में वर्गीकृत किया था, जिसके कारण मुकदमा भी चला। हालांकि अदालत ने इस पार्टी को चरमपंथी संगठन घोषित करने पर रोक लगा दी थी, लेकिन सरकारी खुफिया एजेंसी ने पाया था कि यह पार्टी विशेष समुदायों के प्रति वैसी ही कड़ी नफरत रखती है, जैसी नफरत नाज़ियों ने यहूदियों के प्रति दिखाई थी।

जर्मनी समेत एक दर्जन से अधिक शहरों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं, जिसमें ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी पर प्रतिबंध लगाने की मांग की जा रही है, क्योंकि सरकार बनाने के लिए बहुमत से तीन सीटें कम होने के कारण ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी सैक्सनी-एनहाल्ट में गठबंधन के लिए अन्य दलों के साथ बातचीत कर रही है। इसके जवाब में, ऑल्टरनेटिव फॉर जर्मनी के समर्थकों ने भी विभिन्न शहरों में जवाबी विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं।

अगर वे सफल होते हैं, तो वे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार किसी राज्य में सरकार बनाएंगे। यूरोप में नई व्यवस्था कुछ हद तक 20वीं सदी के समान ही रूप ले रही है; बस कुछ समूहों ने पाला बदल लिया है। राज्यविहीन यहूदी जो अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे जब नाज़ी उनका शिकार कर रहे थे, अब जब उनके (यहूदी) पास एक देश है, तो वे गाज़ावासियों का शिकार कर रहे हैं।

नाज़ियों के हाथों बहुत अधिक जुल्म का सामना करने के बाद, उन्होंने खुद जुल्म करने वालों की भूमिका अपना ली। बदलती हुई यह स्थिति फ्रैंट्ज़ फैनन की किताब द रेच्ड ऑफ द अर्थ की याद दिलाती है, जो इस बात को उजागर करती है कि कैसे सताए गए लोग खुद जुल्म करने की इच्छा रखने लगते हैं।

आज यहूदी-विरोधी भावनाएं ज़ायनवाद-विरोधी सोच के साथ मिल गई हैं, क्योंकि दुनिया भर के कई यहूदियों को बड़े पैमाने पर गाजा में जो कुछ भी हो रहा है, उसके समर्थकों के रूप में देखा जाता है। इजराइली राष्ट्र को लेकर शत्रुता धीरे-धीरे विकसित हुई है; होलोकॉस्ट (यहूदी नरसंहार) की यादें पीछे छूटती जा रही हैं और धीरे-धीरे अपनी प्रासंगिकता खो रही हैं। आज, अधिकांश टकराव एक राष्ट्र-राज्य के रूप में इजराइल के कदमों पर केंद्रित है, जो कि उस युग के बिल्कुल विपरीत है जब यहूदी बेघर होकर अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे।

अब, इजराइल के पास अपना देश, सुरक्षा और मातृभूमि है, तब भी इतने बड़े पैमाने पर अभाव और हमलों का सामना करने के बाद जुल्म करने वाले की भूमिका में आने को संयुक्त राष्ट्र के कई सदस्य देश आलोचना की नजर से देखते हैं। इजराइल कोई अकेला मामला नहीं है; चरमपंथ एक स्वीकार्य वास्तविकता के तौर पर फैल रहा है।

भारत और वियतनाम ने रणनीतिक साझेदारी को गहरा किया

अरुणिम भूयान

भारत-वियतनाम उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी को रविवार को रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह और वियतनाम के राष्ट्रीय रक्षा उपमंत्री सीनियर लेफ्टिनेंटजनरल गुयेन ट्रुओंग थांग के बीच हुई मीटिंग से नई रफ़्तार मिली है। यह मीटिंग नई दिल्ली में ब्रिक्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वियतनाम के प्रधानमंत्री ले मिन्ह हंग के साथ द्विपक्षीय मीटिंग के ठीक बाद हुई। दोनों मीटिंग का एक साथ होना जरूरी है- द्विपक्षीय जहां लीडर्स ने रिश्ते के लिए बड़ी राजनीतिक दिशा तय की, वहीं रक्षा वार्ता का मकसद उस रणनीतिक इरादे को इंडो-पैसिफिक में बढ़ती भू-राजनैतिक अनिश्चितता के समय में गहरे सैन्य, समुद्री, तकनीकी और औद्योगिक सहयोग में बदलना है।

रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान के मुताबिक, सिंह और ट्रुओंग थांग के बीच मीटिंग में दोस्ती के रिश्ते को मजबूत करने, क्षेत्रीय सुरक्षा को आगे बढ़ाने और द्विपक्षीय संवर्धित व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर फोकस किया गया। मंत्रालय ने कहा, चर्चा संयुक्त पहल को तेज करने, प्रौद्योगिकी साझाकरण और रक्षा औद्योगिक सहयोग पर केंद्रित थी। दोनों पक्षों ने शांतिपूर्ण, स्थिर और नियम-आधारित क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए समुद्री और रक्षा संबंधों को बढ़ाने के अपने साझा वादे को फिर से दोहराया।

बयान के अनुसार, दोनों पक्षों ने जटिल सुरक्षा गतिशीलता से निपटने के लिए बहुपक्षीय मंचों में करीबी तालमेल की अहमियत पर ज़ोर दिया। खास तौर पर, उन्होंने दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन (आसियान) और रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस (ADMM-प्लस) के तहत सक्रिय भागीदारी के महत्व पर जोर दिया। मंत्रालय ने आगे कहा, दोनों पक्षों ने आसियान के नेतृत्व वाले सिस्टम के जरिए व्यावहारिक रक्षा सहयोग बढ़ाने के अपने साझा कमिटमेंट को फिर से पक्का किया, और कहा कि एडीएमएम-प्लस विशेषज्ञों के कार्य समूह जैसे मिलकर काम करने वाले प्लेटफॉर्म, इंडो-पैसिफिक में क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने और सामूहिक सुरक्षा आर्किटेक्चर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं।

शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स समिट के दौरान अपने वियतनामी समकक्ष हंग के साथ मीटिंग की। विदेश

मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज में कहा, इस मीटिंग में दोनों नेताओं को आपसी रिश्तों में हुई तरक्की को रिव्यू करने का मौका मिला, जिसे मई 2026 में वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ़ वियतनाम के अध्यश्र टो लैम के भारत दौरे के दौरान एक एडवांस व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया गया था।

दोनों नेताओं ने आपसी महत्व के अलग-अलग क्षेत्रीय और ग्लोबल मुद्दों पर भी अपने विचार शेयर किए, और अपनी साझेदारी को और मज़बूत करने का वादा दोहराया। भारत और वियतनाम के बीच पुरानी दोस्ती है, जो साझा सभ्यतागत विरासत, आपसी विश्वास और समझ पर आधारित है। वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक अहम पिलर है और साउथ-ईस्ट एशिया के साथ भारत के बड़े जुड़ाव में एक अहम साझेदार है। वियतनाम को नई दिल्ली पहले से ही एक्ट ईस्ट पॉलिसी, विजन महासागर (क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के लिए पारस्परिक और समग्र उन्नति) और भारत की व्यापक भारत-प्रशांत भागीदारी के प्रमुख स्तंभ के रूप में मानता है।

मई 2026 के संयुक्त वक्तव्य में साफ तौर पर रक्षा और सुरक्षा सहयोग को सुरक्षा सहयोग का एक अहम हिस्सा बताया गया और इसमें रक्षा-नीति वार्ता, एक्सरसाइज, स्टाफ की बातचीत, जॉइंट रिसर्च और सह-निर्माण, नौसेना और वायु सेना के साथ बातचीत, जानकारी साझाकरण, जल विज्ञान, क्षमता निर्माण और रक्षा-औद्योगिक सहयोग को बढ़ाने की बात कही गई। यह बात अपने आप में महत्वपूर्ण है कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के दौरान दोनों प्रधानमंत्रियों की मुलाकात हुई। वियतनाम ने नई दिल्ली समिट में ब्रिक्स साझेदार देश के तौर पर हिस्सा लिया, जिससे हनोई को बड़े ग्रुप और खासकर भारत के साथ जुड़ने का एक नया मौका मिला। भारत के लिए, इससे द्विपक्षीय संबंध को एक और बहुपक्षीय आयाम मिलता है। नई दिल्ली अपनी ब्रिक्स चेयरपर्सनशिप का इस्तेमाल सिर्फ ग्रुप के अंदर बातचीत के लिए ही नहीं, बल्कि ग्लोबल साउथ और खास इंडो-पैसिफिक पार्टनर्स के साथ अपने जुड़ाव को बढ़ाने के लिए भी कर रही है। इस मामले में वियतनाम का हिस्सा लेना बहुत जरूरी है। हनोई ने पारंपरिक रूप से सोच-समझकर बनाई गई विदेश नीति अपनाई है, जिसमें उसने अपनी रणनीतिक आजादी को बचाते हुए बड़ी ताकतों के साथ रिश्ते बनाए रखे हैं। इसलिए, ब्रिक्स के साथ इसका जुड़ाव जरूरी नहीं कि किसी खास पावर ब्लॉक के साथ तालमेल दिखाता हो। बल्कि, यह वियतनाम को आर्थिक, तकनीकी और कूटनीतिक जुड़ाव के लिए एक और प्लेटफॉर्म देता है।

नई दिल्ली के लिए भी यह समीकरण उतना ही जरूरी है। भारत वियतनाम को एक ऐसे देश के तौर पर देखता है जो आसियान केंद्रीयता, नेविगेशन की आज़ादी, नियमों पर आधारित समुद्री व्यवस्था और रणनीतिक स्वायत्तता में उसके दिलचस्पी को शेयर करता है। इस तरह, मोदी-हंग मीटिंग ने राजनीतिक ढांचा दिया, जबकि सिंह-ट्रुओंग थांग की बातचीत ने उस ढांचे को एक मज़बूत सुरक्षा आयाम देना शुरू किया। हाल की रक्षा बातचीत में समुद्री सहयोग पर जोर शायद रणनीतिक रूप से सबसे अहम हिस्सा है। भारत और वियतनाम हिंद महासागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर को जोड़ने वाले समुद्री रास्तों पर भौगोलिक रूप से महत्वपूर्ण जगहों पर हैं।

वियतनाम का समुद्र तट उसे दक्षिण चीन सागर पर नजर रखने के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान देता है, जबकि प्रमुख भारतीय महासागर समुद्री मार्गों के किनारे भारत की स्थिति दोनों देशों को पूरक समुद्री हित प्रदान करती है। उनके मई 2026 के संयुक्त वक्तव्य में साउथ चाइना सी में शांति, स्थिरता, सुरक्षा, दक्षिण चीन सागर में नौवहन और उड़ान की सुरक्षा और आज़ादी बनाए रखने की अहमियत पर ज़ोर दिया गया, साथ ही झगड़ों को अंतरराष्ट्रीय कानून, खासकर समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के हिसाब से शांति से सुलझाने की बात कही गई। दक्षिण चीन सागर एशिया के सबसे विवादित समुद्री क्षेत्रों में से एक बना हुआ है, जहां चीन अपने बड़े दावे करता है और वियतनाम भी प्रतिस्पर्धी दावों वाले दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में से एक है।

ब्रिक्स : असंभव को संभव कर दिखाना सबके बस की बात नहीं

नीरज कुमार दुबे

नई दिल्ली में संपन्न ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बीच भारत ने उस वक्त बड़ी कूटनीतिक कामयाबी हासिल की, जब पश्चिम एशिया के युद्ध को लेकर आमने-सामने खड़े ईरान और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) एक साझा ब्रिक्स घोषणा पर सहमत हो गए। करीब छह महीने से जारी युद्ध और लगातार बढ़ते क्षेत्रीय तनाव के बीच दोनों देशों के बीच सहमति बनना सिर्फ ब्रिक्स के लिए नहीं, बल्कि भारत की कूटनीतिक भूमिका के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है।

दरअसल, ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की मई में हुई बैठक के दौरान ईरान और यूएई के बीच मतभेद इतने गहरे थे कि संयुक्त बयान तक जारी नहीं हो पाया था। पश्चिम एशिया में युद्ध को लेकर दोनों देशों की प्राथमिकताएं और संघर्ष की व्याख्या अलग-अलग थी। ऐसे में दिल्ली शिखर सम्मेलन से पहले सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि ऐसी भाषा तैयार की जाए, जिस पर ईरान और यूएई समेत ब्रिक्स के सभी सदस्य देश एक साथ खड़े हो सकें।

भारत की अध्यक्षता में हुई लंबी और बेहद कठिन बातचीत के बाद आखिरकार वह रास्ता निकाला गया। बातचीत आधी रात के बाद तक चलती रही और करीब चार बजे तक सहमति बनाने की कोशिशें जारी रहीं। अंतिम घोषणा में किसी एक देश को सीधे तौर पर युद्ध के लिए जिम्मेदार ठहराने के बजाय पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव पर सामूहिक चिंता जताई गई। सभी पक्षों से अधिकतम संयम बरतने और ऐसे कदमों से बचने की अपील की गई, जो स्थिति को और बिगाड़ सकते हैं।

इस पूरी कवायद का सबसे बड़ा राजनीतिक संकेत उस समय सामने आया, जब ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और यूएई के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान के बीच ब्रिक्स सम्मेलन के इतर मुलाकात हुई। युद्ध शुरू होने के बाद दोनों देशों के शीर्ष नेतृत्व के बीच यह सबसे महत्वपूर्ण संपर्कों में से एक माना जा रहा है। खास बात यह है कि यह बैठक ऐसे समय हुई, जब क्षेत्रीय संघर्ष ने ईरान और खाड़ी देशों के रिश्तों को बेहद संवेदनशील बना दिया है।

हम आपको बता दें कि ब्रिक्स की नई दिल्ली घोषणा में पश्चिम एशिया की स्थिति पर चिंता जताते हुए नागरिकों की सुरक्षा, संप्रभुता और क्षेत्रीय स्थिरता पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही वैश्विक व्यापार और समुद्री आवाजाही को सुरक्षित रखने की जरूरत भी रेखांकित की गई। घोषणा का मकसद किसी पक्ष की जीत या हार तय करना नहीं, बल्कि ऐसी न्यूनतम साझा जमीन तैयार करना था, जिस पर अलग-अलग रणनीतिक हित रखने वाले देश भी एक साथ खड़े हो सकें।

यहीं भारत की भूमिका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। ब्रिक्स के विस्तार के बाद संगठन के भीतर अब सिर्फ आर्थिक हितों का मेल नहीं है, बल्कि ईरान, यूएई और अन्य देशों के बीच गंभीर भू-राजनीतिक मतभेद भी मौजूद हैं। ऐसे माहौल में सर्वसम्मति से घोषणा पारित कराना अपने आप में एक राजनीतिक उपलब्धि है। भारतीय कूटनीति ने पक्ष के साथ खड़े होने की बजाय ऐसी भाषा पर जोर दिया, जिसे विरोधी धड़े भी स्वीकार कर सकें।

देखा जाये तो इसका असर ब्रिक्स की विश्वसनीयता पर भी पड़ेगा। अगर युद्ध जैसे बेहद संवेदनशील मुद्दे पर ईरान और ॅश्व जैसे विरोधी हितों वाले देश एक ही घोषणा पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, तो दिल्ली शिखर सम्मेलन ने यह संदेश जरूर दिया है कि ब्रिक्स सिर्फ आर्थिक सहयोग का मंच नहीं रह गया है। अब वह ऐसे भू-राजनीतिक संकटों में भी साझा रुख बनाने की कोशिश कर रहा है, जहां वैश्विक शक्तियों के बीच सीधा टकराव मौजूद है।

गांव के नजदीक भालू के छोड़े जाने को लेकर बवाल

ग्रामीणों ने वन विभाग के खिलाफ खोला मोर्चा

बालोद। जिले में गांव के करीब भालू छोड़े जाने को लेकर देर रात ग्रामीणों और वन विभाग के बीच विवाद की स्थिति बन गई। मरदेल गांव से करीब 500 मीटर दूर भालू छोड़े जाने की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीणों ने वन विभाग की तीन गाड़ियों को रोककर विरोध जताया। ग्रामीणों का कहना था कि गांव के इतने करीब भालू छोड़े जाने से जान-माल का खतरा बढ़ सकता है।

जानकारी के मुताबिक, बालोद वन परिक्षेत्र के रानीमाई जंगल से अस्वस्थ भालू का रेस्क्यू किया गया था। इसके बाद उसे इलाज के लिए रायपुर के जंगल सफारी भेजा गया। उपचार के बाद स्वस्थ होने पर वन विभाग की टीम सोमवार रात उसे डौंडी वन परिक्षेत्र के मरदेल गांव के पास लेकर पहुंची और बस्ती से करीब 500 मीटर की दूरी पर छोड़ दिया। भालू को गांव के इतने करीब छोड़े जाने की जानकारी मिलते ही ग्रामीण मौके पर जुट गए और वन विभाग की टीम को रोक लिया। ग्रामीणों ने भालू से संभावित खतरे को लेकर अधिकारियों से सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी मांगी। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर ग्रामीणों का आक्रोश बढ़ गया। मामले की जानकारी मिलते ही जनपद सदस्य तुलेश्वर हिचामी मरदेल पहुंचे। उन्होंने डौंडी रेंजर जीवन भोंडेकर से फोन पर चर्चा की। बताया गया कि रेंजर ने भालू को छोड़ने की जिम्मेदारी बालोद रेंजर और अन्य अधिकारियों पर डाल दी। इससे ग्रामीण और नाराज हो गए। घटना के दौरान गुरुर रेंजर चंद्रशेखर भंडारी, बालोद रेंजर सरोज कुमार और दल्लीराजहरा रेंजर संतोष ठाकुर मौके पर मौजूद थे। वहीं, क्षेत्र के रेंजर जीवन भोंडेकर के मौके पर मौजूद नहीं होने को लेकर ग्रामीणों ने नाराजगी जताई और उनके खिलाफ नारेबाजी की। मामले की गंभीरता को देखते हुए बालोद वन विभाग के स्र्डह्र किशोरी साहू देर रात घटनास्थल पहुंचे। उन्होंने जनपद सदस्य और ग्रामीणों से चर्चा कर मामले को शांत कराया। स्र्डह्र ने मंगलवार को पिंजरा लगाकर भालू को पकड़ने और उसे किसी अन्य स्थान पर ले जाने का लिखित आश्वासन दिया।

सूरज की रोशनी से रोशन हुई स्वास्थ्य सेवाएं

एमसीबी। दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और सुचारू बनाने की दिशा में जिला प्रशासन की पहल अब धरातल पर असर दिखा रही है। जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ) मद से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जनकपुर, विकासखंड भरतपुर में स्थापित 7.2 किलोवाट क्षमता के सौर संयंत्र ने अस्पताल की विद्युत व्यवस्था को मजबूती दी है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत इस कार्य पर 26.05 लाख रुपये की लागत आई है। जिला मुख्यालय से लगभग 110 किलोमीटर दूर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जनकपुर आसपास के दूरस्थ ग्रामीण एवं वनांचल क्षेत्रों के लोगों के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य केन्द्र है।

यहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में ग्रामीण उपचार के लिए पहुंचते हैं। अस्पताल में मरीजों के उपचार के साथ-साथ विभिन्न आवश्यक चिकित्सा उपकरणों, डीप फ्रीजर और अन्य व्यवस्थाओं के संचालन के लिए

नियमित बिजली आपूर्ति जरूरी है। सौर संयंत्र की स्थापना से पहले बिजली की अनियमितता के कारण स्वास्थ्य केन्द्र में कई बार चिकित्सकीय सेवाओं के संचालन में व्यवधान की स्थिति बनती थी। विद्युत आपूर्ति बाधित होने पर मरीजों के साथ अस्पताल के स्टॉफ को भी परेशानी का सामना करना पड़ता था।

सबसे महत्वपूर्ण चुनौती टीकों एवं आवश्यक दवाइयों को सुरक्षित तापमान पर रखने की थी, जिसके लिए डीप फ्रीजर का लगातार संचालित रहना जरूरी है। अब सौर संयंत्र की स्थापना से अस्पताल में विद्युत उपलब्धता पहले की तुलना में अधिक सुचारु हुई है। इससे चिकित्सा सेवाओं को निरंतर संचालित करने में मदद मिल रही है और डीप फ्रीजर में रखे जाने वाले महत्वपूर्ण वैक्सीन एवं दवाइयों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करने में सुविधा हो रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जनकपुर में कार्यरत स्टाफ और उपचार के लिए पहुंचने वाले मरीजों ने सौर संयंत्र को दूरस्थ क्षेत्र के लिए उपयोगी पहल बताया है। उनका कहना है कि पहले बिजली बाधित होने की स्थिति में स्वास्थ्य सेवाओं के संचालन को लेकर चिंता बनी रहती थी, लेकिन अब सौर ऊर्जा संयंत्र से विद्युत व्यवस्था को मजबूती मिलने से उपचार, दवाइयों के संरक्षण और आवश्यक चिकित्सा व्यवस्था के संचालन में काफी सुविधा हुई है। डीएमएफ मद से 26.05 लाख रुपये की लागत से स्थापित 7.2 किलोवाट क्षमता का यह सौर संयंत्र केवल बिजली का वैकल्पिक स्रोत नहीं, बल्कि दूरस्थ वनांचल में स्वास्थ्य सेवाओं की निरंतरता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

ये है पीएमजेसीवाय रोड का हाल

मरम्मत की मांग को लेकर ग्रामीणों ने किया अनोखा प्रदर्शन

गरियाबंद। तस्वीरों में नजर आ रही सड़क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की है। यह हाल क्षेत्र में हुई बारिश के बाद का है। पांच साल पहले अंतिम बार सड़क का मरम्मत किया गया था। अब हालत जर्जर होने पर ग्रामीणों ने शासन-प्रशासन से सड़क दोबारा ठीक करने की मांग की लेकिन इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया। मंगलवार को कुरलापारा से थाना मार्ग पर 100 मीटर हिस्से में परेशान ग्रमीणों ने धान रोपाई कर अनोखा प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का कहना है कि कुरलापारा से थाना मार्ग पर 100 मीटर हिस्से में बारिश के पानी से सड़क गायब हो जाती है। हल्की बारिश में भी मार्ग कीचड़ से लथपथ हो जाता है। हालात ऐसे हो गए हैं कि चलना भी मुश्किल

हो चुका है। न पैदल चलने वाले और न ही दोपहिया वाहन मार्ग का इस्तेमाल कर पाते हैं। जानकारी के मुताबिक, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (क्क्लस्ड्ड) से अमलीपदर-खरीपथरा मार्ग पर सड़क बनाया गया था,सड़क दो बार बनाया जा चुका है। अंतिम बार 2021 में सड़क बनाया गया था। पांच साल पहले बनाया गया सड़क अब जर्जर हुआ तो रिनिवल की मांग शुरू हो गई है। क्क्लस्ड्ड उपयंत्री सौरभ दास ने बताया कि पांच साल पहले सड़क निर्माण हुआ था। सड़क रिनिवल के लिए प्रस्ताव बनाकर विभाग को भेजा गया है। मंजूरी मिलने के बाद सड़क निर्माण कार्य कराया जाएगा।

सेवानिवृत्ति के अंतिम वर्ष में गृह जिले में मिलेगी पोस्टिंग :हाईकोर्ट

बिलासपुर। हाईकोर्ट ने एक मामले में आदेश दिया है कि रिटायरमेंट के आखिरी वर्ष में कर्मचारी को गृह जिले में नियुक्ति देनी चाहिए। आबकारी विभाग के हेड कांस्टेबल की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उनको गृह जिले बिलासपुर में पदस्थ करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने संबंधित अधिकारी को आदेश की प्रति मिलने के 15 दिनों के भीतर आवश्यक पोस्टिंग के आदेश जारी करने के निर्देश दिए हैं।

याचिकाकर्ता हेड कांस्टेबल अभी रायगढ़ जिले में पदस्थ हैं। उन्होंने रिटायरमेंट करीब होने के कारण रायगढ़ से बिलासपुर तबादले की मांग की थी। याचिका में वर्ष 2025 की ट्रांसफर पॉलिसी के क्लॉज 3।12 का लाभ देने की मांग करते हुए याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि उनकी नियुक्ति 19 अप्रैल 1993 को आबकारी विभाग में सेल्समैन के रूप में हुई थी। बाद में उन्हें नियमित कर आबकारी आरक्षक बनाया गया। वर्ष 2014 में उनका तबादला कोरबा से बिलासपुर हुआ था।

24 जून 2022 को उन्हें बिलासपुर से रायगढ़ भेजा गया। 2023 में पदोन्नति के बाद वे रायगढ़ में ही पदस्थ हैं। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि वह जुलाई 2027 में

सेवानिवृत्त होने वाले हैं। साथ ही उनकी पत्नी का स्वास्थ्य भी खराब है और उनका लगातार इलाज चल रहा है। उन्होंने गृह जिले बिलासपुर में पोस्टिंग के लिए कई बार विभाग को अभ्यावेदन दिए, लेकिन उन पर निर्णय नहीं लिया गया। राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि 5 जून 2025 की ट्रांसफर पॉलिसी आबकारी विभाग पर लागू नहीं होती, क्योंकि इस नीति में पुलिस, आबकारी, परिवहन, वाणिज्यिक कर और शिक्षा विभाग को बाहर रखा गया है। सरकार ने यह भी कहा कि कर्मचारी को उसकी पसंद की पोस्टिंग पाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। कोर्ट ने सरकार के इस तर्क को निरस्त करते हुए कहा कि अगले साल जुलाई 2027 में रिटायरमेंट के मद्देनजर उन्हें होम जिले में पोस्टिंग देनी चाहिए।

कांस्टेबल भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा 400 से अधिक अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग का रास्ता साफ

छत्तीसगढ़ में कांस्टेबल भर्ती मामले में अभ्यर्थियों के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) खारिज करते हुए वेटिंग लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग का रास्ता साफ कर दिया है। इस आदेश से 400 से अधिक अभ्यर्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वेटिंग लिस्ट में शामिल पात्र अभ्यर्थियों की नियुक्ति की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। कोर्ट ने तीन महीने के भीतर ज्वाइनिंग कराने का आदेश दिया है।

इससे लंबे समय से नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों में राहत और खुशी का माहौल है। कांस्टेबल भर्ती से जुड़े इस मामले में छत्तीसगढ़ सरकार ने संबंधित आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। सरकार की ओर से दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके साथ ही वेटिंग लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर स्थिति स्पष्ट हो गई है।

श्रमिकों के ई-केवाईसी पंजीयन-नवीनीकरण के लिए एमसीबी में ग्राम पंचायतवार शिविरों का संशोधित कार्यक्रम जारी

एमसीबी। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के अंतर्गत पंजीकृत श्रमिकों के पंजीयन, नवीनीकरण, संशोधन एवं विभिन्न योजनाओं से संबंधित आवेदन प्राप्त करने तथा ई-केवाईसी की प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा कराने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले शिविरों का संशोधित कार्यक्रम जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर के निर्देशों के अनुपालन में जारी कार्यक्रम के अनुसार जिले के मनेन्द्रगढ़, खड़गवां और भरतपुर विकासखंड की विभिन्न ग्राम पंचायतों में 30 सितंबर 2026 तक चरणबद्ध रूप से शिविर आयोजित किए जाएंगे। संशोधित कार्यक्रम के अनुसार मनेन्द्रगढ़ विकासखंड में 10 से 30 सितंबर तक विभिन्न ग्राम पंचायतों में शिविर लगाए जाएंगे। इनमें 15 सितंबर को छिपछिपी और भौंता, 16 सितंबर को डुगला, बिझियाटोला, केवटी, बुलाकीटोला एवं केल्हारी, 17 सितंबर को रोजी, डिहुली, बिरौडांड, शिवगढ़ एवं बड़काबहेरा, 21 सितंबर को सोनहरी, गरुडडोल, बाला, महाई एवं केलुआ तथा 22 सितंबर को सिरियाखोह एवं हरितनापुर में शिविर आयोजित होंगे। इसके बाद 23 से 30 सितंबर तक निर्धारित ग्राम पंचायतों में क्रमवार शिविर लगाए जाएंगे। खड़गवां विकासखंड में 9 सितंबर से शिविरों का आयोजन शुरू किया गया है। 15 सितंबर को अखराडांड, 16 सितंबर को सुंदरपुर, देवाडांड, सलका, लकड़ापारा एवं गिद्धमुड़ी, 17 सितंबर को छोटेकेलुआ, आमाडांड, जड़हरी एवं कदरेवा में शिविर निर्धारित हैं। 21 से 30 सितंबर तक भी विकासखंड की विभिन्न ग्राम पंचायतों में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार शिविर आयोजित किए जाएंगे। भरतपुर विकासखंड में 11 से 30 सितंबर तक शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। 15 सितंबर को भगवानपुर, घाघरा एवं एतवार, 16 सितंबर को जनुआ, बेलनगांव, चरखर, मेहदौली एवं डोंगरीटोला, 21 सितंबर को देवगढ़, हरई, कुंवारी, पतवाही एवं ओहनिया तथा 22 सितंबर को हरचौका एवं चिडौला में शिविर लगाए जाएंगे। 23 से 30 सितंबर तक भी निर्धारित ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित होंगे। श्रम पदाधिकारी द्वारा जारी आदेश में सभी संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों को निर्धारित तिथि को सुबह 10 बजे शिविर स्थल पर पहुंचना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

गौ हत्या मामले में एक्शन:मांस और टांगी के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार

अंबिकापुर। सरगुजा जिले के सुनसान जंगल मे गौ हत्या में शामिल ग्रामीणों को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अंधेरे का फायदा उठाते हुए तीन आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस ने गौ मांस और टांगी बरामद किया है। जानकारी के अनुसार ग्राम रजौटी के सान्याघुटरी जंगल में रविवार को शाम करीब 8 बजे पांच ग्रामीणों ने मिलकर गाय की हत्या कर दी और मांस

का आपस में बंटवारा किया। मुखबिर से सूचना के बाद पुलिस ने आरोपियों को घेराबंदी दबोचा। हालांकि अंधेरे का फायदा उठाकर तीन लोग फरार हो गए। पुलिस ने रजौटी बरपारा निवासी 45 वर्षीय अजय कुमार कुजूर आ। बंदुराम व 27 वर्षीय रंजीत कुजूर आ। छोटेलाल कुजूर को हिरासत में लिया। वहीं गुमगरा निवासी विवेक खलखो समेत तीन लोग भाग निकले। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से कटे हुए गाय के अवशेष पड़े हुए थे जिन्हें सबूत के तौर पर पुलिस ने जब्त कर लिया। गिरफ्तार दोनों आरोपियों को थाने लाकर पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि गौ हत्या के बाद पहले आपस में मांस का बंटवारा करते जो बचता उसे बेच देते। इस मामले में पुलिस ने धारा 325,3(5) और छग कृषक पशु परि। अधि।2004 की धारा 4,5,10 के तहत अपराध दर्ज करते हुए गिरफ्तार दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

पद्मश्री पंडिराम मांडवी के घर हुई मूर्ति चोरी का खुलासा

नारायणपुर। बस्तर की पारंपरिक कला और संस्कृति को देश दुनिया में पहचान दिलाने वाले मूर्तिकार पद्मश्री पंडिराम मांडवी की कलाकृतियां उनके घर से चोरी हुई थी। चोरी की गई 17 कलाकृतियों में से 12 को बरामद किया है। मामले में कोंडागांव जिले के नरहरपारा से एक आरोपी को गिरफ्तार किया है,जबकि उसका साथी फरार है। पुलिस के मुताबिक 27 अगस्त की देर रात गढ़बेंगाल स्थित पंडिराम मांडवी की कार्यशाला में रखी कई लकड़ी की कलाकृतियां चोरी हुई थीं। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक संदीप पटेल के निर्देश और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ऐश्वर्य चंद्राकर के मार्गदर्शन में जांच टीम गठित की गई। नारायणपुर थाना प्रभारी विनीत दुबे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने चोरी हुई कलाकृतियों और आरोपियों की तलाश शुरू की। जांच के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी की गई कलाकृतियों में से कुछ को बेचने की कोशिश की जा रही है।

कोरबा के अंडरपास बने जनता के लिए सिरदर्द, लोग परेशान

कोरबा। कोरबा की पहचान ऊर्जाधानी के तौर पर है, यहां से निकलने वाले कोयले और बिजली से देश का कई राज्य रोशन होते हैं। शहर के बीच से रेल लाइन गुजरती है। हर 15 मिनट से आधे घंटे में रेल के इंजन कोयले से लदी मालगाड़ी को लेकर क्रॉस करते हैं। इस दौरान रेलवे फाटक बंद होने से लंबा जाम लग जाता है, शहर की रफ्तार थम जाती है। इससे निजात दिलाने के लिए शहर में दो अंडरपास की परिकल्पना की गई। एक सुनालिया अंडरपास, दूसरा कुचैना अंडरपास, जिसमें से एक का निर्माण हो चुका है, दूसरा दो विभागों के बीच फंसा है। शहर के बीच सुनालिया अंडरपास की प्रक्रिया पिछले 2 साल से चल रही है, जो अब तक धरातल पर नहीं उतरी है। दो विभागों के बीच यह अंडरपास फंस गया है। वहीं कोयलांचल क्षेत्र(उपनगर) कुसमुंडा दीपका की लगभग 2 लाख की आबादी के लिए कुचैना में अंडरपास का निर्माण कर दिया गया है। इस अंडरपास का निर्माण इस तरह से किया गया कि 3 फीट से ज्यादा ऊंचाई तक पानी भर जा रहा है।

बालोद के गुंडरदेही में पुल के ऊपर से बह रहा पानी

बालोद। लगातार हो रही बारिश की वजह से जिले में सामान्य जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। भारी बारिश के बाद ज्यादातर नदी नाले उफान पर हैं। कई जगहों पर तो बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लोगों के खेत पानी में डूब चुके हैं। गुंडरदेही इलाके में सबसे ज्यादा स्थिति खराब है। यहां देवरी मार्ग पर बारिश का पानी सड़क के ऊपर से गुजर रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो सालों से यहां ब्रिज बनाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी मांग अभी तक पूरी नहीं हुआ है। लोगों की शिकायत है कि हर साल बारिश के दिनों में यहां इसी तरह से पानी सड़क के ऊपर से गुजरता है। ऐसे में उनका यहां से पार होना मुश्किल हो जाता है। सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं और स्कूल जाने वाले बच्चों को होती है। कभी उनके कपड़े गीले हो जाते हैं, तो कभी उनके बस्ते भीग जाते हैं। गांव वालों का कहना है कि अगर यहां पर पुल बन जाता है तो उनकी सारी दिक्कतें एक झटके में दूर हो जाएंगी। गांव वालों का कहना है कि त्योहारों के मौसम में उनको कई बार बाजार आना जाना पड़ता है।

तिरुपति बालाजी मंदिर की तर्ज पर 100 फीट का गणेश पंडाल

जांजगीर चांपा। गणेश चतुर्थी के दिन घर घर बप्पा का आगमन हो गया है। पंडालों में भी गणेश जी विराजमान हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में कचहरी चौक पर भव्य गणेश पंडाल बनाया गया है। 100 फीट के इस गणेश पंडाल में सोमवार को 20 फीट के गणपति बप्पा विराजमान हुए। गणेश जी की स्थापना विधि विधान से की गई। क्यों खास है कचहरी चौक का गणेश पंडाल जिला मुख्यालय के कचहरी चौक पर इस बार तिरुपति बालाजी मंदिर के तर्ज पर पंडाल बनाया गया है। पंडाल 100 फीट ऊंचा और 80 फीट चौड़ा है। इस पंडाल को कोलकाता से आए कारीगरों ने दिनरात की मेहनत से बनाया है। पंडाल को खूबसूरत झालरों से सजाया गया है कचहरी चौक के राजा के रूप में भगवान गणेश की लगभग 20 फीट की प्रतिमा स्थापित की गई है। भगवान गणेश के साथ मां पार्वती और भगवान शंकर भी है। इसके अलावा तिरुपति बालाजी, भगवान जगन्नाथ के दर्शन भी श्रद्धालुओं को मिलेंगे। भटगांव के कलाकारों ने सभी प्रतिमाओं को तैयार किया है।

त्योहारों के मद्देनजर कोरबा पुलिस की सख्ती

कोरबा। त्योहार के मौसम में जिले में कानून व्यवस्था मजबूत करने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। गणपति स्थापना के पहले दिन सोमवार को लगभग दिन भर पुलिस ने शहर के दर्जनों आदतन और सक्रिय अपराधियों पर शिकंजा कसा है। कार्रवाई के तहत पुलिस ने विभिन्न थानों में आपराधिक पृष्ठभूमि वाले निगरानी शुदा 64 गुंडा-बदमाशों को तलब किया और उन्हें कड़ी चेतावनी दी। अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने वाले गुंडा बदमाशों को विभिन्न स्थानों में बुलाया गया। एडिशनल एसपी लखन पटले ने इनकी परेड कराई और उन्हें बताया कि आपराधिक गतिविधियों से तौबा कर लें, अन्यथा उनके खिलाफ अत्यंत कठोर कानूनी कदम उठाए जाएंगे। जिले के सभी अलग-अलग थानों में ऐसे गुंडा बदमाशों को थाने बुलाया गया था। उन्हें शांति व्यवस्था बनाकर रखने की चेतावनी दी गई है। जिनके विरुद्ध विभिन्न मामले हैं, उन्हें थाने बुलाया गया। उन्हें स्पष्ट हिदायत दी गई है।

पीएम मत्स्य संपदा योजना से 150 मत्स्य पालकों ने बदली अपनी किस्मत

महासमुंद। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की 25 वर्षों की सार्वजनिक सेवा यात्रा में गांव, गरीब, किसान और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास किए गए हैं। इसी सोच के अनुरूप केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना अब महासमुंद जिले के किसानों के लिए अतिरिक्त आमदनी, स्वरोजगार और रोजगार का मजबूत माध्यम बन रही है। धान की पारंपरिक खेती के साथ किसान मछली पालन, हैचरी और पाउंड लाइनर जैसी गतिविधियों को अपनाकर अपनी आय के नए स्रोत विकसित कर रहे हैं। जिले में करीब 150 किसान योजना का लाभ लेकर मछली पालन को व्यवसाय के रूप में अपना चुके हैं। सरकार से मिलने वाले अनुदान से तालाब निर्माण से लेकर हैचरी और अन्य मत्स्य गतिविधियों के लिए बुनियादी सुविधाएं विकसित हो रही हैं, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। इसी बदलाव की मिसाल बिरकोनी निवासी किसान दिनेश चन्द्राकर हैं। पारंपरिक खेती में लागत बढ़ने के बाद उन्होंने मछली पालन की ओर कदम बढ़ाया। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत करीब 7.50 लाख रुपये की लागत से एक हेक्टेयर में तालाब

खुदवाया। इसके पश्चात करीब 14 लाख रुपये की लागत से 20 हजार वर्गफुट में मछली हैचरी स्थापित की। सरकार से मिले अनुदान ने इस व्यवसाय को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मत्स्य पालक श्री दिनेश के मुताबिक हैचरी में मछली के बच्चों को तैयार कर तालाब में डाला जाता है। करीब 8 से 9 महीने में लगभग 15 टन मछली तैयार हो जाती है, जिसे मछुआरों के माध्यम से बाजार में बेचा जाता है। एक किलो मछली तैयार करने में करीब 70 से 80 रुपये की लागत आती है, जबकि बाजार में इसे 120 से 150 रुपये प्रति किलो तक बेचने से उन्हें अच्छी आमदनी हो रही है। इसी तरह ग्राम बकमा के किसान हिमांशु चंद्राकर ने भी प्रधानमंत्री मत्स्य योजना का लाभ लेकर करीब 28 लाख रुपये की लागत से दो पाउंड लाइनर यूनिट तैयार कराई। उन्हें सरकार की ओर से 60 प्रतिशत अनुदान मिला। हिमांशु बताते हैं कि सभी खर्च निकालने के बाद उन्हें सालाना करीब 3 से 4 लाख रुपये की बचत हो जाती है। इस तरह मछली पालन उनके लिए आय का मजबूत और स्थायी जरिया बन गया है। मछली पालन का लाभ सिर्फ तालाब और यूनिट संचालकों तक सीमित नहीं है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। बिरकोनी में मछली पालन से जुड़े मजदूरों का कहना है कि पहले काम की तलाश में उन्हें दूसरे स्थानों पर जाना पड़ता था, लेकिन अब गांव में ही सालभर रोजगार मिल रहा है। करीब 9 हजार रुपये प्रतिमाह की आय के साथ नियमित काम मिलने से परिवार के खर्च चलाने में भी सहूलियत हो रही है। सरकार की योजना किसानों को मछली पालन से जोड़ने के साथ इस क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर भी जोर दे रही है। नए तालाब निर्माण, बायोफ्लॉक यूनिट, हैचरी, कोल्ड स्टोरेज और मछली दाना निर्माण जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देकर उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय में वृद्धि का प्रयास किया जा रहा है।

ढाढ़पखना पहुंचे 18 हाथी ने फसल रौंदी

कोरबा। एतमानगर रेंज के बंजारी परिसर में विचरण कर रहे 18 हाथियों के दल ने एक बार फिर वन विभाग की चिंता बढ़ा दी है। दल के 18 हाथी बीती रात जंगल के रास्ते गुरसिया के समीप गांव ढाढ़पखना पहुंच गए, जबकि दल से अलग चल रहा रहा एक लोनर हाथी रिंगनिया की ओर निकल गया है।

खबर है कि रिंगनिया पहुंचते ही लोनर ने एक ग्रामीण के खेत में लगी धान की फसल को नुकसान पहुंचाया है, हालांकि ढाढ़पखना पहुंचे हाथियों के दल ने फिलहाल किसी तरह की जन-धन हानि नहीं की है। लेकिन इस दल के रिहायशी इलाके के पास विचरण करने के कारण ग्रामीणों में दहशत बनी हुई है। हाथियों

की मौजूदगी को गांव के समीप आता देख वन विभाग ने आसपास के गांवों में निगरानी बढ़ा दी है। ढाढ़पखना समेत प्रभावित क्षेत्र के गांवों में मुनादी कराकर ग्रामीणों को सतर्क किया जा रहा है, ग्रामीणों को हाथियों के नजदीक नहीं जाने और जंगल की ओर जाने से बचने की सलाह दी गई है। वन अमला हाथियों की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए है। एक दिन पहले यही हाथियों का यह दल बंजारी में विचरण कर रहा था। इस दौरान कुछ वन कर्मचारी बिजली टावर के नीचे काम कर रहे थे। अचानक हाथियों का दल वहां पहुंच गया था। जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हाथियों को नजदीक आता देख वन कर्मचारियों ने टावर पर चढक़र अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम और हाथी मित्र दल के सदस्य मौके पर पहुंचे थे। टीम ने हाथियों को वहां से हटाया, जिसके बाद टावर पर फंसे कर्मचारियों को सुरक्षित नीचे उतारा गया। अब हाथियों के अलग-अलग दिशाओं में बढने के बाद वन विभाग ने आसपास के गांवों में विशेष निगरानी और सतर्कता बढ़ा दी है।

विशेष फीचर

प्रधानमंत्री आवास योजना
विकसित छत्तीसगढ़ की मजबूत नींव

पक्के घरों से बदल रही गांवों की तस्वीर, आत्मसम्मान से भर रहा हर परिवार

"हमारी सरकार का लक्ष्य है, कि प्रदेश का कोई भी पात्र परिवार आवास जैसी मूलभूत सुविधा से वंचित न रहे। पक्का घर केवल चार दीवारें नहीं, बल्कि परिवार की सुरक्षा, सम्मान और बेहतर भविष्य की नींव है।

श्री विष्णु देव साय
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

हर गरीब परिवार के पास अपना पक्का घर हो, यह केवल एक योजना नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का अभियान है। विकसित भारत के निर्माण में आवास, सम्मान और आत्मनिर्भरता की महत्वपूर्ण भूमिका है। **श्री नरेंद्र मोदी,** प्रधानमंत्री

पक्का घर : सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि का आधार

छत्तीसगढ़ में आवास योजना का नया अध्याय

छत्तीसगढ़ आज प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रभावी क्रियान्वयन राष्ट्रीय उदाहरण बनकर उभरा है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य ने आवास निर्माण को केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि जनकल्याण के व्यापक अभियान का स्वरूप दिया है। गांव-गांव तक पहुंची इस पहल ने लाखों जरूरतमंद परिवारों के जीवन में सुरक्षा, सम्मान और स्थायित्व का नया अध्याय जोड़ा है।

एक समय था जब प्रदेश के अनेक ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में परिवार कच्चे मकानों, झोपड़ियों और अस्थायी आवासों में जीवनयापन करने को मजबूर थे। बरसात में टपकती छतें, गार्मियों में असहनीय तापमान और प्राकृतिक आपदाओं के बीच जीवन संघर्ष का पर्याय बन चुका था। आज वही परिवार मजबूत पक्के मकानों में सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जी रहे हैं।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 'सबके लिए आवास' के संकल्प को छत्तीसगढ़ सरकार ने मिशन मोड में धरातल पर उतारते हुए प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित किया है।

आवास से आगे बढ़कर सामाजिक परिवर्तन

प्रधानमंत्री आवास योजना ने केवल ईंट और सीमेंट के ढांचे खड़े नहीं किए हैं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन की नई इबारत लिखी है। प्रदेश के दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों, आदिवासी बहुल इलाकों और नक्सल प्रभावित अंचलों तक विकास की मुख्यधारा पहुंचाने में इस योजना की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

आज हजारों गांवों में नए आवासों के साथ बिजली, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, गैस कनेक्शन, सड़क और डिजिटल सेवाओं का विस्तार हुआ है। इससे ग्रामीण जीवन की गुणवत्ता में अभूतपूर्व सुधार देखने को मिला है।

आवास अब केवल रहने की जगह नहीं, बल्कि परिवार की सुरक्षा, बच्चों की शिक्षा, महिलाओं की गरिमा और सामाजिक सम्मान का आधार बन गया है।

नया घर, नई उम्मीद

सुशासन, तकनीक और पारदर्शिता का मॉडल

छत्तीसगढ़ सरकार ने योजना के क्रियान्वयन में आधुनिक तकनीक और सुशासन को प्राथमिकता दी है।

तकनीक से पारदर्शिता

- **डिजिटल मॉनिटरिंग** — हर आवास की प्रगति पर निरंतर नजर
- **जियो टैगिंग** — प्रत्येक आवास का भौगोलिक सत्यापन
- **सीधा लाभ** — हस्तांतरण लाभ सीधे हितग्राही के खाते में
- **जन सहभागिता** — आवास मित्र, पंचायत और स्थानीय हितग्राहियों की सक्रिय भूमिका
- **पारदर्शिता और जवाबदेही** — शिकायत निवारण और ऑनलाइन निगरानी

डिजिटल मॉनिटरिंग, जियो टैगिंग, ऑनलाइन सत्यापन, हेल्पलाइन सेवाएं और तकनीकी निगरानी तंत्र के माध्यम से प्रत्येक आवास की प्रगति पर लगातार नजर रखी जा रही है। इससे योजना में पारदर्शिता बढ़ी है और लाभ सीधे पात्र हितग्राहियों तक पहुंच रहा है।

आदिवासी अंचलों में विकास का नया अध्याय

छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना ने विकास की नई कहानी लिखी है। पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वाले हजारों परिवार अब पक्के और सुरक्षित घरों में जीवन यापन कर रहे हैं।

पीएम जनमन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के समन्वित क्रियान्वयन से विशेष पिछड़ी जनजातियों तक विकास की किरण पहुंची है।

इन क्षेत्रों में आवास निर्माण के साथ-साथ सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और आजीविका के अवसरों का भी विस्तार हुआ है।

रोजगार और आत्मनिर्भरता को मिली नई दिशा

26 लाख से अधिक आवासों की स्वीकृति

विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों के लिए 33000 आवासों की स्वीकृति

आत्मसमर्पित पूर्व नक्सलियों के लिए विशेष 15000 आवास

महिला स्व-सहायता समूहों की भागीदारी

निर्माण सामग्री आपूर्ति और भवन निर्माण सहयोग से विकास की मुख्यधारा से जुड़ते परिवार और बढ़ती आत्मनिर्भरता।

जब घर बना, तब बदली जिंदगी

बस्तर, सरगुजा, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा, जशपुर, बलरामपुर, कोरिया, सक्ती, मुंगेली और प्रदेश के अन्य जिलों में ऐसे हजारों परिवार हैं जिनके लिए पक्का मकान कभी एक सपना था आज वही सपना साकार हो चुका है। पक्का घर मिलने के बाद बच्चों की पढ़ाई बेहतर हुई है, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कम हुई है और परिवार में आत्मविश्वास बढ़ा है।

महिलाओं के नाम पर बढ़ रहा स्वामित्व और सम्मान

योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में आवास महिलाओं के नाम अथवा संयुक्त स्वामित्व में स्वीकृत किए गए हैं। इससे महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण मजबूत हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में आज महिलाएं केवल घर की जिम्मेदारी नहीं संभाल रहीं, बल्कि परिवार की आर्थिक योजनाओं, बच्चों की शिक्षा और सामाजिक निर्णयों में भी सक्रिय भूमिका निभा रही हैं।

जल संरक्षण के साथ हरित विकास

छत्तीसगढ़ सरकार ने आवास निर्माण को पर्यावरण संरक्षण से भी जोड़ा है। 'मोर गांव-मोर पानी' जैसे अभियानों के माध्यम से नए आवासों में वर्षा जल संचयन को प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह पहल भविष्य के लिए जल संरक्षण और सतत विकास की दिशा में बढ़ा कदम है।

डिजिटल छत्तीसगढ़, मजबूत कदम

ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था, डिजिटल सत्यापन और तकनीकी निगरानी ने योजना की विश्वसनीयता बढ़ाई है। डिजिटल माध्यमों से शिकायत निवारण और प्रगति समीक्षा की व्यवस्था ने सुशासन की नई मिसाल प्रस्तुत की है।

रोजगार और आत्मनिर्भरता को मिली नई दिशा

प्रधानमंत्री आवास योजना ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा प्रदान की है। आवास निर्माण कार्यों से हजारों स्थानीय श्रमिकों, राजमिस्त्रियों, निर्माण सामग्री विक्रेताओं और स्वयं सहायता समूहों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार द्वारा कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से बड़ी संख्या में युवाओं को निर्माण कार्यों का प्रशिक्षण दिया गया है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ा है और ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां तेज हुई हैं। कई जिलों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह निर्माण सामग्री आपूर्ति, भवन निर्माण सहयोग और अन्य सेवाओं से जुड़कर आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।

संवाद-48873/2

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

विकसित भारत – विकसित छत्तीसगढ़ की ओर

प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से समृद्ध, सुरक्षित और आत्मनिर्भर ग्रामीण भारत की ओर

मुख्यमंत्री ने किया 'डीपी वर्ल्ड नवा रायपुर ओपन 2026' की ट्रॉफी का अनावरण, गोल्फ में हाथ आजमाकर बढ़ाया खिलाड़ियों का उत्साह

देश-विदेश के 132 प्रोफेशनल गोल्फर ले रहे हिस्सा 18 विदेशी खिलाड़ी भी दिखाएंगे अपना कौशल

देश-दुनिया के गोल्फ मानचित्र पर नई पहचान बना रहा छत्तीसगढ़

रायपुर। छत्तीसगढ़ तेजी से देश के उभरते स्पोर्ट्स डेस्टिनेशन के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। प्रदेश में खेल अधोसंरचनाओं के विस्तार, प्रतिभाओं को बेहतर प्रशिक्षण और अवसर उपलब्ध कराने तथा राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित खेल आयोजनों की मेजबानी से छत्तीसगढ़ की खेल संस्कृति को नई ऊर्जा मिली है। अब प्रोफेशनल गोल्फके बड़े टूर्नामेंट का नवा रायपुर में आयोजन इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नवा रायपुर स्थित फेयरवे गोल्फ एंड कंट्री क्लब रिजॉर्ट में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित 'डीपी वर्ल्ड नवा रायपुर ओपन 2026' कार्यक्रम को संबोधित करते हुए यह बात कही।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विश्वास व्यक्त किया कि 'डीपी वर्ल्ड नवा रायपुर ओपन 2026' आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ की नई पहचान बनेगा और नवा रायपुर को देश-दुनिया के प्रमुख गोल्फ डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रतियोगिता की आकर्षक ट्रॉफी का अनावरण किया तथा देश-विदेश से आए प्रोफेशनल गोल्फ खिलाड़ियों का छत्तीसगढ़ की धरती पर आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया। इस अवसर पर 1983 क्रिकेट विश्वकप विजेता भारतीय टीम के कप्तान एवं प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कपिल देव और सीईओ अमनदीप जोहल तथा की विशेष उपस्थिति ने आयोजन की गरिमा को और बढ़ाया। मुख्यमंत्री ने गोल्फ कोर्स पर स्वयं गोल्फ में हाथ आजमाया और शानदार शॉट लगाकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। मुख्यमंत्री को गोल्फ खेलते देखकर उपस्थित खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों और अतिथियों में विशेष उत्साह दिखाई दिया।

1983 विश्वकप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान और पीजीटीआई अध्यक्ष कपिल देव की गरिमामयी उपस्थिति में हुआ आयोजन

पहले फिल्मों में देखते थे गोल्फ आज छत्तीसगढ़ कर रहा बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी

मुख्यमंत्री श्री साय ने गोल्फसे जुड़ी अपनी स्मृतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि एक समय था, जब हम गोल्फके बारे में केवल सुना करते थे या फिल्मों में लोगों को गोल्फखेलते देखते थे। आज बदलते छत्तीसगढ़ में हम स्वयं प्रोफेशनल गोल्फके इतने बड़े आयोजन की मेजबानी कर रहे हैं। यह प्रदेश के विकास के साथ यहां तेजी से विस्तार ले रही खेल संस्कृति का सुखद संकेत है।

हर वर्ष छत्तीसगढ़ में हो गोल्फ का बड़ा टूर्नामेंट: कपिल देव

प्रोफेशनल गोल्फटूर ऑफइंडिया के अध्यक्ष एवं 1983 विश्वकप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कपिल देव ने 'डीपी वर्ल्ड नवा रायपुर ओपन 2026' के आयोजन में सहयोग के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और छत्तीसगढ़ सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के बड़े प्रोफेशनल आयोजन किसी भी प्रदेश में खेल संस्कृति को मजबूत करने और नई प्रतिभाओं को प्रेरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कपिल देव ने कहा कि छत्तीसगढ़ में गोल्फ के साथ-साथ अन्य खेलों के विकास की भी व्यापक संभावनाएं हैं। उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि इस प्रतिष्ठित गोल्फ प्रतियोगिता का आयोजन छत्तीसगढ़ में प्रत्येक वर्ष हो और आने वाले वर्षों की तारीखें पहले से निर्धारित की जाएं। इससे देश-विदेश के प्रोफेशनल खिलाड़ी अपने अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट कैलेंडर के अनुरूप छत्तीसगढ़ आने की योजना बना सकेंगे।

तारा कोल ब्लॉक नीलामी, आदिवासियों के जीवन आधार पर हमला, सरकार ने खुद लिखकर कराई नीलामी: भूपेश बघेल

रायपुर। राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हसदेव अरण्य के तारा कोल ब्लॉक की नीलामी को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि तारा क्षेत्र के जंगल आदिवासियों के जीवन का आधार हैं, जिसे भाजपा सरकार ने नीलाम कर दिया है। साथ ही उन्होंने 2024 और 2025 के पीएससी घोटाले की जांच की मांग की।

कांग्रेस राजीव भवन में मंगलवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार ने तारा कोल ब्लॉक की नीलामी की है जो CG Syn-Gas and Chemicals Limited को मिला है, जो अडानी इंटरप्राइजेस की सहयोगी कंपनी मुंद्रा सिनर्जी की सब्सिडियरी है।बघेल ने कहा कि तारा ब्लॉक लगभग 5000 एकड़ में है, जिसमें 4000 एकड़ घना जंगल है। यहां 10 लाख से अधिक पेड़ काटे जाएंगे। यह लेमरू एलीफेंट रिजर्व के चारों ओर है, जिससे हाथियों के कॉरिडोर और अन्य वन्य प्रजातियों पर संकट आएगा। कांग्रेस सरकार ने लेमरू के लिए 1950 वर्ग किमी क्षेत्र संरक्षित किया था। एक आदिवासी मुख्यमंत्री होते हुए साय सरकार आदिवासियों की बजाय अडानी के हितों का ध्यान रख रही है। बघेल ने आगे कहा कि भाजपा ने 2023 चुनाव में यूपीएससी की तर्ज पर पीएससी परीक्षा का वादा किया था, लेकिन पिछले 2 साल से गड़बड़ी हो रही है। उन्होंने मांग की कि इंटरव्यू स्थगित किया जाए, सभी अभ्यर्थियों की उत्तर -पुस्तिकाएं इंटरव्यू से पहले सार्वजनिक की जाएं, चयनितों के अलावा बाकी सभी को कॉपियां नि:शुल्क दी जाएं, मॉडल उत्तर जारी हो और 1:3 के अनुपात का पालन करते हुए पुनर्मूल्यांकन हो। गड़बड़ियों को सरकार का संरक्षण है।

नुआखाई समृद्ध कृषि परंपरा, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और अन्नदाता के परिश्रम का उत्सव: साय

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नई फसल के स्वागत और प्रकृति के अनुपम उपहार के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने वाले पावन पर्व नुआखाई के अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर अन्नदाता किसानों की सुख-समृद्धि, अच्छी फसल और सभी परिवारों की खुशहाली की मंगलकामना की है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि नुआखाई समृद्ध कृषि संस्कृति और लोक परंपराओं से जुड़ा महत्वपूर्ण पर्व है। नई फसल के आगमन की खुशी में मनाया जाने वाला यह पर्व प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, अन्न के सम्मान और किसान के अथक परिश्रम के प्रति आदर का भाव प्रकट करता है। खेतों में उपजी नई फसल केवल

नुआखाई पर्व की दी हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं

किसान की मेहनत का प्रतिफल नहीं, बल्कि प्रकृति की कृपा और हमारी कृषि प्रधान संस्कृति की समृद्धि का भी प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति में खेती-किसानी केवल आजीविका का माध्यम नहीं, बल्कि हमारे सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का अभिन्न हिस्सा है। हमारे अनेक पर्व और परंपराएं कृषि चक्र, प्रकृति और लोकजीवन से गहराई से जुड़ी हुई हैं। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि नुआखाई अपनी मिट्टी, अपनी जड़ों और अपनी गौरवशाली परंपराओं से जुड़े रहने की प्रेरणा देता है। यह पर्व सामाजिक आत्मीयता, पारिवारिक एकजुटता और आपसी सद्भाव को भी मजबूत करता है। नई फसल की खुशियां जब परिवार और समाज मिलकर साझा करते हैं, तब लोकसंस्कृति और अधिक जीवंत तथा समृद्ध होती है। मुख्यमंत्री साय ने नुआखाई के पावन अवसर पर कामना करते हुए कहा कि प्रकृति की कृपा छत्तीसगढ़ पर सदैव बनी रहे। हमारे किसान साथियों के खेत हरे-भरे और फसलों से लहलहाते रहें, अन्न के भंडार भरें तथा अन्नदाताओं के घर-आंगन में समृद्धि आए। प्रदेश के प्रत्येक परिवार के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली का संचार हो तथा आपसी प्रेम, भाईचारा और सद्भाव निरंतर मजबूत होता रहे।

गिरीश पंकज को मिलेगा 'नईधारा रचना सम्मान और 'राष्ट्रमाता जिजाऊ पुरस्कार

रायपुर। वरिष्ठ साहित्यकार गिरीश पंकज को उनके दीर्घ साहित्यिक योगदान, हिंदी भाषा की सेवा और सामाजिक सरोकारों के लिए एक साथ दो प्रतिष्ठित राष्ट्रीय सम्मानों के लिए चुना गया है। इन को पटना में 'नई धारा रचना सम्मान-2026' तथा बड़ोदरा में 'राष्ट्रमाता जिजाऊ पुरस्कार-2027' प्रदान किया जाएगा। बाल साहित्य लेखन के लिए 3 अक्टूबर को इन्हें भीलवाड़ा की पत्रिका 'बाल वाटिका' द्वारा भी सम्मानित किया जाएगा. रायपुर में रहकर पिछले 45 वर्षों से साहित्य एवं पत्रकारिता में सक्रिय गिरीश पंकज का साहित्यिक सफर मनेंद्रगढ़ से शुरू हुआ। स्वतंत्रता

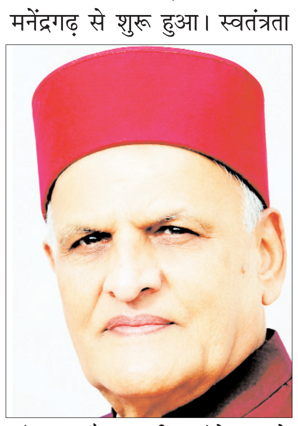

संग्राम और खादी आंदोलन से जुड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार की पृष्ठभूमि में पले-बढ़े गिरीश पंकज ने साहित्य को केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं बनाया, बल्कि सामाजिक सरोकारों और जनहित के विषयों को भी अपनी लेखनी में प्रमुखता दी। गिरीश पंकज के साहित्यिक सफर की सबसे उल्लेखनीय उपलब्धियों में 22 खंडों में प्रकाशित 'गिरीश पंकज रचनावली' भी शामिल है.प्राप्त जानकारी के अनुसार पद्मश्री डॉ. अशोक चक्रधर की अध्यक्षता वाली सम्मान चयन समिति ने गिरीश पंकज की प्रकाशित रचना 'लुधिया' को 'नई धारा रचना सम्मान-2026' के लिए चयनित किया है। इस सम्मान से उन्हें 29 नवंबर को पटना में आयोजित समारोह में अलंकृत किया जाएगा।

साहित्यिक उपलब्धि के साथ-साथ सामाजिक क्षेत्र में जनहित और राष्ट्रहित के लिए किए जा रहे कार्यों को भी सम्मान मिला है। इन्हीं योगदानों के लिए गिरीश पंकज को 'राष्ट्रमाता जिजाऊ पुरस्कार-2027' के लिए चुना गया है। गिरीश पंकज को मिलने वाले तीन राष्ट्रीय सम्मान इस बात का प्रमाण हैं कि छोटे शहरों और अंचलों से निकलने वाली साहित्यिक प्रतिभा भी देश के बड़े मंच पर अपनी जगह बना सकती है।

छत्तीसगढ़/राजधानी
प्रमुख समाचार

आज से 'श्रावक संस्कार शिविर' 10 दिन चलेगी आध्यात्मिक साधना

रायपुर। राजधानी में अध्यात्म, संयम और स्वाध्याय की अविरल धारा बहने जा रही है। समयोपदेश वर्षायोग 2026 के अंतर्गत पर्वाधिराज दशलक्षण महापर्व के अवसर पर 'श्रावक संस्कार शिविर 2026' का आयोजन किया जा रहा है। मुनि आगम सागर ससंघ के पावन सानिध्य में होने वाला यह 10 दिवसीय आवासीय एवं आध्यात्मिक शिविर 16 से 25 सितंबर 2026 तक दिगम्बर जैन बड़ा मंदिर, मालवीय रोड, रायपुर में आयोजित होगा। शिविर का उद्देश्य श्रावकों के जीवन में जैन जीवनशैली, संयम, स्वाध्याय और धार्मिक संस्कारों को मजबूत करना है। शिविर में शामिल होने वाले प्रतिभागियों के लिए भोर से लेकर रात्रि तक आध्यात्मिक साधना, धार्मिक शिक्षण और अनुशासनबद्ध दिनचर्या निर्धारित की गई है। शिविर की शुरुआत सुबह 5:30 बजे प्रार्थना से होगी। इसके बाद योग एवं आत्म-ध्यान, नित्य नियम पूजन, मूलनायक भगवान का अभिषेक और शांतिधारा कराई जाएगी। सुबह 8:15 से 9 बजे तक तत्त्वार्थ सूत्र की विशेष स्वाध्याय कक्षा होगी। इसके बाद सुबह 9 बजे मुनि आगम सागर की मंगल देशना और प्रवचन होगा।

नगर निगम में आज से 30 तक लगेगा विशेष राजस्व वसूली शिविर

रायपुर। नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने चालू वित्त वर्ष के संपत्तिकर का पूर्ण भुगतान करने पर 5 प्रतिशत छूट का लाभ देने के लिए 16 से 30 सितंबर तक विशेष राजस्व वसूली शिविर लगाने के निर्देश दिए हैं। यह शिविर सभी 10 जोनों और निगम मुख्यालय में सुबह 10 से शाम 5:30 बजे तक लगेगा। आयुक्त ने सभी जोन कमिश्नरों को निर्देशित किया है कि उन वार्डों/क्षेत्रों में जहां कम बकायादार हैं या वसूली की संभावना अधिक है, वहां विशेष शिविर आयोजित किए जाएं।आयुक्त ने सभी जोन कमिश्नरों को व्यक्तिगत निगरानी कर शिविर को सफल बनाने के निर्देश दिए हैं। **छूट का लाभ:** नागरिकों को निर्धारित अवधि में कर जमा करने पर 5 प्रतिशत रिबेट मिलेगा, इसके लिए प्रेरित किया जाए। पूर्व वर्षों की तरह निगम मुख्यालय के प्रवेश द्वार के पास भी शिविर लगेगा, जहां राजस्व और बाजार विभाग के स्टाफकर, बाजार शुल्क और अन्य देयकों का भुगतान लेंगे।

नवोदय में प्रवेश के लिए आवेदन शुरू, नि:शुल्क होगी सभी सुविधाएं

रायपुर। जवाहर नवोदय विद्यालय समिति (जेएनवीएस) की ओर से सत्र 2027-28 में कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नवोदय विद्यालय में प्रवेश की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए यह महत्वपूर्ण अवसर है। पात्र विद्यार्थी निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए विद्यार्थियों को नवोदय विद्यालय समिति की निर्धारित पात्रता पूरी करना जरूरी होगा। आवेदन ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। विद्यार्थियों और अभिभावकों को आवेदन करते समय सभी जरूरी जानकारी सावधानीपूर्वक भरने की सलाह दी गई है। कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थी का संबंधित जिले का निवासी होना आवश्यक है। इसके साथ ही विद्यार्थी का शैक्षणिक सत्र 2026-27 में उसी जिले के किसी मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 8वीं में अध्ययनरत होना जरूरी है। पात्रता पूरी करने वाले विद्यार्थी ही चयन प्रक्रिया में शामिल हो सकेंगे।

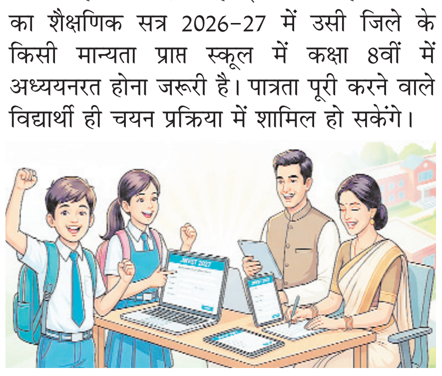

सेवा संकल्प अभियान: जीपीएम में जलाए जाएंगे 2 लाख आशीर्वाद के दीये

रायपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के अवसर पर जिले में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर 2026 तक सेवा संकल्प अभियान का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के माध्यम से सेवा, समर्पण, जनभागीदारी और जनकल्याण की भावना को व्यापक स्वरूप दिया जाएगा। एक माह तक चलने वाले इस अभियान में जिलेभर में विविध जनकल्याणकारी, सामाजिक और जनभागीदारी आधारित गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। अभियान के प्रथम दिवस 17 सितंबर को जिले में शाम 7 बजे 2 लाख आशीर्वाद के दीये प्रज्वलित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस अवसर पर मल्टीपर्पस स्कूल मैदान पेंड्रा में जिला स्तरीय दीप प्रज्वलन कार्यक्रम आयोजित होगा, जहां 11 हजार दीये प्रज्वलित किए जाएंगे। यह आयोजन सेवा, संकल्प और जनभागीदारी की भावना का भव्य प्रतीक बनेगाजिले के विभिन्न स्थानों पर भी एक साथ प्रज्वलित होंगे दीये। जिला स्तरीय आयोजन के साथ ही गौरेला पेन्ड्रा मरवाही जिले के तीनों जनपद पंचायत क्षेत्रों में भी जनभागीदारी के साथ दीप प्रज्वलन किया जाएगा।

संत समिति का निर्णय-अनंत चतुर्दशी पर ही हो गणेश विसर्जन

रायपुर। राजधानी रायपुर में मंगलवार को संत समिति महानगर की बैठक आयोजित की गई थी। जिसमें गणेश उत्सव को हर्षोल्लास और सनातनी परंपरा के अनुसार मनाने का आह्वान किया गया। संतों ने कहा कि विसर्जन अनंत चतुर्दशी के दिन ही किया जाए और विसर्जन के दौरान फूहड़ गाने न बजाए जाएं। बैठक में निर्णय लिया गया कि सभी सनातनियों से निवेदन है कि गणेश उत्सव बड़े हर्ष के साथ मनाएं और विसर्जन अनंत चतुर्दशी पर ही करें, जिससे परिवार, रायपुर, छत्तीसगढ़ और राष्ट्र को उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। संत समिति ने अपील की कि विसर्जन सनातनियों द्वारा ही ढोल-बाजे और भजन-कीर्तन के साथ किया जाए, किसी भी प्रकार के फूहड़ गाने न बजाए जाएं। समिति ने चेतावनी दी कि संत समिति पूरे रायपुर का भ्रमण करेगी और जहां गणेश प्रतिमा सनातन परंपरा के अनुसार नहीं पाई गई, वहां शासन-प्रशासन के साथ मिलकर कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में प्रमुख रूप से महंत देवदास महाराज, महंत वेदप्रकाश महाराज, डॉ. स्वामी राजेश्वरानंद, किन्नर अखाड़ा महामंडलेश्वर साध्वी सौम्या, आजीवन निराहार संत स्वामी गौतम आनंद, महामंडलेश्वर जीतेश्वर आनंद जी उपस्थित थे।

कचरे से संसाधन बनाने की तकनीकों पर मंथन

विश्व सर्कुलर इकोनॉमी फोरम में छत्तीसगढ़ की सक्रिय सहभागिता

रायपुर। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित 10वें वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम 2026 में छत्तीसगढ़ ने अपनी सक्रिय सहभागिता दर्ज कराई। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा के नेतृत्व में राज्य से गई टीम ने फोरम में शामिल होकर सर्कुलर इकोनॉमी, संसाधन दक्षता और कचरे को संसाधन में बदलने के आधुनिक समाधानों पर वैश्विक विशेषज्ञों के साथ विचार-विमर्श किया। राज्य शहरी विकास अभिकरण के सीईओ सुमीत अग्रवाल भी प्रतिनिधि मंडल में शामिल हैं।

राज्य की टीम के प्रमुख बोरा ने कहा कि छत्तीसगढ़ शासन शहरी क्षेत्रों में टिकाऊ अपशिष्ट प्रबंधन, संसाधनों के अधिकतम उपयोग और सर्कुलर इकोनॉमी की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य का प्रयास है कि नवाचार और आधुनिक तकनीकों के माध्यम से कचरे का बेहतर प्रबंधन करते हुए उसे उपयोगी संसाधन में परिवर्तित किया जाए। इससे पर्यावरण संरक्षण के साथ स्वच्छ, मजबूत और टिकाऊ शहरों के निर्माण को गति मिलेगी तथा विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में राज्य की पहल और मजबूत होगी। फोरम में दुनिया के विभिन्न देशों के नीति-निर्माता, उद्योग जगत के विशेषज्ञ, नवाचारी तकनीक विकसित करने वाले संस्थान और क्षेत्र में काम कर रहे विशेषज्ञ एवं प्रतिनिधि शामिल हुए। इसमें सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने, संसाधनों के बेहतर उपयोग, टिकाऊ उत्पादन एवं उपभोग तथा वेस्ट-टू-रिसोर्स जैसे विषयों पर व्यापक चर्चा हुई।

राज्य की टीम ने प्रदर्शनी केंद्रों का किया अवलोकन- छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधिमंडल ने फोरम के दौरान प्रदर्शनी केंद्रों का भी अवलोकन किया। यहां रिसाइक्लिंग, संसाधनों की रिकवरी, कचरे से उपयोगी उत्पाद तैयार करने, टिकाऊ सामग्री तथा सर्कुलर बिजनेस मॉडल से जुड़ी नवीन तकनीकों और समाधानों को प्रदर्शित किया गया था। टीम ने इन तकनीकों और मॉडलों के जरिए कचरे को बोझ के बजाय उपयोगी संसाधन में बदलने की संभावनाओं को समझा। विश्व सर्कुलर इकोनॉमी फोरम में सहभागिता के दौरान राज्य की टीम को वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर अपनाई जा रही श्रेष्ठ कार्यप्रणालियों को समझने तथा छत्तीसगढ़ के शहरी विकास और अपशिष्ट प्रबंधन तंत्र के लिए उपयोगी नवाचारों की संभावनाएं तलाशने का अवसर मिला।

नुआखाई हमारी समृद्ध कृषि संस्कृति और सामाजिक एकता का पर्व: मिश्रा

रायपुर। रायपुर के गायत्री नगर स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर परिसर में नुआखाई पर्व श्रद्धा एवं उल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में पंडित जी द्वारा प्रभु श्री जगन्नाथ जी की विधि-विधान एवं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूजा-अर्चना कराई गई। उपस्थित लोगों ने एक-दूसरे को प्रणाम कर नुआखाई पर्व की शुभकामनाएं दीं। तत्पश्चात नव अन्न (पहली फसल) ईष्ट देवता को अर्पित कर प्रसाद स्वरूप अन्न ग्रहण किया गया।

इस अवसर पर रायपुर नगर उत्तर विधायक पुरन्दर मिश्रा ने कहा कि नुआखाई हमारी समृद्ध कृषि परंपरा, संस्कृति और

सामाजिक एकता का पर्व है। यह पर्व हमें अन्न के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और किसान के परिश्रम का सम्मान करने की प्रेरणा देता है। प्रभु श्री जगन्नाथ जी से प्रार्थना है कि नुआखाई का यह पावन पर्व सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। विधायक मिश्रा ने प्रदेशवासियों सभी बंधुओं को नुआखाई पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.